PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 330
दि. 02.09.2026,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 : नई दिल्ली में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ संवाद

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात में वैश्विक निवेश के लिए आह्वान किया, वैश्विक निवेशकों को सहयोग देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाई

गुजरात सरकार दुनियाभर के उद्योगों और निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने और पारस्परिक विकास के लिए और मजबूत साझेदारी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है : श्री भूपेंद्र पटेल

गांधीनगर : 11वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (वीजीजीएस) 2027 की तैयारियों के हिस्से के रूप में, गुजरात सरकार ने 31 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ संवाद किया। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत, विशेषकर गुजरात के दुनियाभर के देशों के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से लोगों का संपर्क, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और तेजी से बढ़ते आर्थिक सहयोग ने वर्षों से इस साझेदारी को और मजबूत बनाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वीजीजीएस 2027 के जरिए, राज्य इस वैश्विक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, निवेश और आपसी विकास के लिए नए अवसरों का निर्माण करना चाहता है।

मिशनों के प्रमुखों के साथ इस संवाद में गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, आईएएस, गुजरात सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार, डॉ. हसमुख अढिया, आईएएस (सेवानिवृत्त), भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) श्री सुधाकर दलेला, (आईएफएस), भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) श्री पी.एस. गंगाधर, (आईएफएस), गुजरात सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. अंजू शर्मा, (आईएएस), तथा गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा, (आईएएस) मौजूद रहे।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपने संबोधन में कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन में राज्य वर्ष 2003 से वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन कर रहा है, जो गुजरात की विकास यात्रा में गेम-चेंजर साबित हुई है। वर्षों से इस समिट ने गुजरात और दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग, निवेश और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त मंच के रूप में भूमिका निभाई है।"

माननीय मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की उल्लेखनीय सफलता ने गुजरात को 'भविष्य के वैश्विक प्रवेशद्वार' के रूप में एक नई पहचान दिलाई है। गुजरात, आज भारत के औद्योगिक विकास को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार है और यह निवेश, नवाचार, टेक्नोलॉजी और वैश्विक साझेदारी के लिए एक विश्वसनीय स्थल के रूप में उभरा है।

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई दिशा तय कर रहे हैं। बदलते वैश्विक परिदृश्य में गुजरता की प्राथममिकताएं स्पष्ट हैं- इनोवेशन के लिए मजबूत इकोसिस्टम, निवेश के लिए नए अवसर और विश्वास पर आधारित साझेदारी।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फार्मास्युटिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में गुजरात नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इतना ही नहीं, गुजरात वैश्विक सेमीकंडक्टर क्षेत्र और वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभा रहा है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय शिष्टमंडल के साथ अमेरिका और कनाडा के अपने दौरे का जिक्र करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे के दौरान जितने भी सीईओ के साथ हमारी मुलाकात हुई, उन सभी ने श्री नरेन्द्र मोदी के विजन, गुजरात की विकास यात्रा और प्रगतिशील नीतियों की प्रशंसा की और गुजरात में उद्योग स्थापित करने और निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक सुरक्षित, सशक्त और प्रगतिशील वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। वास्तव में, मैं कहूंगा कि भारत ने एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में अपनी पहचान पहले ही स्थापित कर ली है। जब भी वैश्विक नेता भारत के साथ साझेदारी के बारे में सोचते हैं, तब स्वाभाविक रूप से गुजरात उनकी पहली पसंद होता है।" हाल ही की नीतिगत पहलों की बात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में पॉलिसी-ड्रिवन गवर्नेंस यानी नीति-आधारित शासन की मजबूत नींव रखी थी। इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए राज्य ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईटी और आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समक्ष सेवाओं) पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी तथा शिपबिल्डिंग एवं शिप-रिपेयर जैसी अनेक उद्योग-उन्मुख नीतियां लागू की हैं।

हाल ही में, गुजरात ने विकसित गुजरात औद्योगिक नीति 2026 भी लागू की है, जिसमें पहली बार उद्योगों के लिए 'यूज योर इंटेंसिव' की सुविधा शुरू की गई है। राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ नई औद्योगिक नीति गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावरहाउस के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप देती है।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सहभागी देशों के निवेशकों और उद्योगों को गुजरात में आकर निवेश करने और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी और नवाचार के जरिए माननीय प्रधानमंत्री के विजन 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड' में योगदान देने का आह्वान किया।

माननीय प्रधानमंत्री के मंत्र "यही समय है, और यही सही समय है" को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने विदेशी राजनयिक मिशनों के प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने देशों के उद्योगों और निवेशकों को गुजरात में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार दुनियाभर के उद्योगों और निवेशकों को हरसंभव सहयोग देने तथा आपसी विकास के लिए और मजबूत साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री एम.के. दास (आईएएस) ने उद्योग, नवाचार, व्यापार और टिकाऊ विकास के अग्रणी स्थल के रूप में गुजरात में हुए उल्लेखनीय बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व, निवेशक अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं और उभरते क्षेत्रों पर दिए गए विशेष ध्यान के कारण यह प्रगति संभव हुई है। उन्होंने विदेशी मिशन के प्रमुखों से 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027' में सहभागी बनने और निवेश, टेक्नोलॉजी, साझेदारी, व्यापार तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के अवसरों की समीक्षा करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि वीजीजीएस 2027 मजबूत और पारस्परिक लाभकारी साझेदारी स्थापित करने तथा साझा विकास के अवसरों का निर्माण करने के लिए गुजरात और वैश्विक समुदाय को एक साथ लाएगा।

इस अवसर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) श्री सुधाकर दलेला (आईएफएस) ने कहा कि व्यापार और वाणिज्य को मजबूत बनाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक साझेदारी और विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने व्यवसायों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में सक्रिय और प्रभावी नीतियों के महत्व पर जोर दिया और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 के लिए विदेश मंत्रालय के पर्याप्त सहयोग का आश्वासन दिया।

श्री दलेला ने कहा कि गुजरात यानी बिजनेस और वीजीजीएस का 11वां संस्करण पहले के संस्करणों से अधिक भव्य और अधिक प्रभावशाली होगा, जो व्यवसायों और निवेश के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय देशों, व्यवसायों और निवेशकों से गुजरात के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की अपील की और सरकारों, व्यवसायों तथा निवेशकों के बीच अधिक मजबूत साझेदारी एवं सहयोग के नए अवसरों का निर्माण करने के लिए उनके साथ निकटता से काम करने की इच्छा व्यक्त की।

नई दिल्ली में विदेशी मिशनों के प्रमुखों के साथ आयोजित बैठक के दौरान गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग की अपर मुख्य सचिव सुश्री ममता वर्मा (आईएएस) ने अपनी विस्तृत प्रस्तुति में जानकारी दी कि किस प्रकार गुजरात भारत का सबसे तेजी से विकसित होता और वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक कनेक्टेड निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें गुजरात के मजबूत आर्थिक आधार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अग्रणी स्थान, निर्यात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं और 2047 तक 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राज्य की दूरदर्शी परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया। उन्होंने एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, एयरोस्पेस, नवाचार और सर्विस सेक्टर के विकास पर राज्य के विशेष फोकस के बारे में भी सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया गया। वीजीजीएस 2027 को वैश्विक व्यापार, सहयोग और आर्थिक साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बनाते हुए, विदेश मिशनों को कंट्री पवेलियन, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, क्षेत्र-विशिष्ट साझेदारी और निवेश के अवसरों के माध्यम से गुजरात के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया।

इस अवसर पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव (आर्थिक कूटनीति) श्री पी.एस. गंगाधर (आईएफएस) ने कहा कि वर्षों से वीजीजीएस भारत के साथ आर्थिक जुड़ाव को मजबूत बनाने के एक अग्रणी वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है, जिसमें दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। उन्होंने गुजरात में सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और दूसरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सहित नए और परिवर्तनकारी क्षेत्रों में विकसित हो रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला।

हाल के वर्षों में गुजरात अपनी स्थापित औद्योगिक क्षमता, निवेशक-अनुकूल नीतियों और उद्योगों के साथ मजबूत साझेदारी के कारण भारत में निवेश के सर्वाधिक पसंदीदा स्थल के रूप में उभरा है। हाल ही में घोषित किए गए नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में गुजरात ने पहला स्थान हासिल किया है। जनवरी-2000 से मार्च-2026 के दौरान राज्य में कुल 74.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। गुजरात लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) इंडेक्स में भी लगातार अग्रणी रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 11वां संस्करण 10 से 12 जनवरी, 2027 के दौरान गांधीनगर में आयोजित होने वाला है। इस समिट की थीम 'विकसित गुजरात – शेपिंग ग्लोबल फ्यूचर' रखी गई है।

गुजरात में शराबबंदी के मुद्दे पर गांधी जी का बयान: शराब की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए सरकार, पुलिस और समाज को मिलकर काम करना होगा

[निडर, निष्पक्ष और तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा] सूरत।

गांधी जी के गुजरात में गांधी जी के नाम पर शराबबंदी का यह नाटक अब नाम मात्र बनकर रह गया है। कारण यह है कि इस शराबबंदी के नाम पर न केवल पुलिस बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता और अन्य लोग जो गंभीर घटना होने पर सामने आकर हंगामा करते हैं और मेंढक की तरह चुप रहते हैं, उन्हें भी संरक्षण दिया जा रहा है। राम जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जहां शराब बनाने वाले बनाते हैं, आपूर्ति करने वाले आपूर्ति करते हैं, खरीदने वाले खरीदते और बेचते हैं, और पीने वाले फिर पीते हैं और मरने वाले मरते हैं। इसलिए, शराब के आदी तक पहुंचने के बजाय, पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अवैध रूप से चल रही इस आपूर्ति श्रृंखला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और शराब के राक्षस को जड़ से उखाड़ फेंके। देसी शराब बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल कहाँ से आता है? गुड़, महुडो या अन्य सामग्री भट्टों तक कौन पहुँचाता है? क्या यह आपूर्ति श्रृंखला वास्तव में पुलिस से अनजान है या जाँच प्रणाली इस कड़ी तक पहुँचने में विफल रही है? शराब विक्रेता पकड़ा गया। आपूर्तिकर्ता क्यों बच निकलता है? शराब की बोतलें जब्त करने से शराब में मिलावट नहीं रुकती, शराब बनाने की पूरी प्रक्रिया को तोड़ना होगा। शराब की लत से ग्रस्त व्यक्ति न केवल अपना स्वास्थ्य और आय खोता है, बल्कि इसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ता है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और कई बार घरेलू कलह के कारण परिवार का मुखिया भी खोना पड़ता है। शराब को सिर्फ पुलिस का मामला समझकर नहीं देखना चाहिए। यह एक सामाजिक समस्या है। इसीलिए समाज को इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। जाति, क्षेत्र या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी व्यक्ति को निशाना बनाने के बजाय, कानून को इस गैरकानूनी काम को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्ती से बोलना चाहिए। और आज ही सच्ची सामाजिक जागरूकता का समय है। देश के युवाओं को "मेरा शहर, मेरा राज्य, मेरा देश" के संकल्प के साथ नशामुक्त गांव या शहर के लिए जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए। यह तभी संभव है जब पुलिस समन्वय के माध्यम से शराब उत्पादन करने वाले हर स्थान पर, चाहे वह हमारे राज्य में हो या अन्य राज्यों में, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं है। हर युवा को जागरूक करना होगा। हर परिवार को जागरूक करना होगा। और अगर किसी इलाके में बार-बार देसी और विदेशी शराब पकड़ी जा रही है, तो उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए और उस इलाके की पुलिस व्यवस्था को इस समस्या को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसकी शुरुआत कौन करेगा?

मुफ्त रेवड़ी या जन कल्याण? चुनावी लालच के बीच बेरोजगारी, महंगाई और जनता के बुनियादी मुद्दे

[निडर, निष्पक्ष तटस्थ छगनलाल मेवाड़ा द्वारा] सूरत।

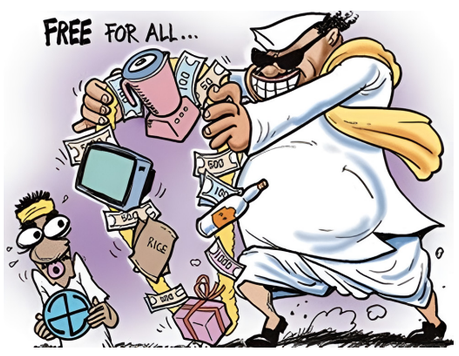

भारत के लिए यह खेद का विषय है कि सरकारें जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाय उन्हें हमेशा के लिए किसी पर निर्भर अपाहिज बनाने में अधिक रुचि दिखा रही हैं। ऐसे में जन कल्याण के दायित्व के तहत किए गए कार्यों और मुफ्त उपहारों के बीच अंतर को दूर करने के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सरकार बनाने के नाम पर राजनीतिक दल मुफ्त उपहार देकर आसानी से वोट बटोर लेते हैं।

आश्चर्यजनक बात यह है कि एक ओर तो सरकारें जन कल्याण सुविधाओं के लिए धन की कमी से जूझ रही हैं या फिर धन जारी करने के बहाने बनाकर जनता को लुभावने वादे कर रही हैं। दूसरी ओर, सत्ता में वापसी और पुनः सत्ता हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर मुफ्त सुविधाएं प्रदान करने का वादा किया जा रहा है।

इस तरह, यह जनता को दिया जाने वाला एक खुला प्रलोभन है, जिसके माध्यम से बुनियादी सुविधाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को छिपाया जाता है। हाल के वर्षों में, लगभग हर पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए इस "मुफ्त" उपकरण का इस्तेमाल किया है।

यह मुफ्त उपहारों का मामला नहीं है, यह बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, अपराध, बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था और देश में कानून-व्यवस्था की चरमराती स्थिति का मामला है। पुलिस थानों में प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का अंबार, अदालतों में लंबित मामले और जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़, ये सब सरकार की विफलता का परिणाम हैं, जिसके शिकार आम जनता है।

चुनाव के समय सत्ता हथियाने की कोशिश करने वाले अपराधियों को दी गई जमानत भी संदेह के घेरे में है। और इन सबके पीछे जनता में जागरूकता की कमी है, जो बार-बार सरकार की आलोचना करने वाली जनता का ही शिकार बन जाती है और जनता द्वारा फिर से वही सरकार सत्ता के सिंहासन पर बिठा दी जाती है।

तब यह सवाल उठता है कि अगर लोग बार-बार फेरीवालों के लालच में राष्ट्रीय हित को भूल जाते हैं, तो नेता हमेशा अपने स्वार्थ के लिए लोगों का शोषण करते रहेंगे।

अहमदाबाद एयरपोर्ट से 'हब एंड स्पोक' अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का शुभारंभ

अमृतसर और वाराणसी के बाद, अहमदाबाद देश का तीसरा एयरपोर्ट बना : वैश्विक कनेक्टिविटी को मिलेगी नई गति

गांधीनगर : अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (एसवीपीआई) से 'हब एंड स्पोक' मॉडल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं की विधिवत शुरुआत हो गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की इस पहल के तहत अमृतसर और वाराणसी के बाद, अहमदाबाद देश का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय यात्री आवागमन के लिए भारत के अग्रणी हब एंड स्पोक ढांचे में एकीकृत किया गया है।

हब एंड स्पोक सेवा के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा तेज गति से आगे बढ़ रही है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 'उड़े देश का आम नागरिक' दृष्टिकोण से 'उड़ान' योजना के तहत 679 से अधिक रूट्स कार्यरत करके, आम यात्रियों को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान कर विमान यात्रा का सपना साकार किया है। अहमदाबाद हवाई अड्डे से 'हब एंड स्पोक' सेवा शुरू होने से राज्य के अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को 'ईज ऑफ ट्रैवल' का सीधा लाभ मिलेगा और छोटे शहरों के यात्रियों को बोर्डिंग, कस्टम और इमिग्रेशन की प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट लीजिंग और फाइनेंसिंग तथा देश की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट से गुजरात एविएशन क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, जो जनवरी 2027 में आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा।

राज्य के एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लगातार गति दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप अभी गुजरात में 3 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित कुल 19 एयरपोर्ट कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि देश की पहली स्मार्ट सिटी धोलेरा में निर्माणाधीन अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने वाले समय में गुजरात और देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेगा।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री के. राम मोहन नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई देने की दिशा में अहमदाबाद से हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत की गई है। अहमदाबाद की वैश्विक कनेक्टिविटी और गुजरात के विशाल एनआरआई समुदाय तथा व्यापार-उद्योग की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह मॉडल महत्वपूर्ण साबित होगा।

उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत अहमदाबाद से दिल्ली होते हुए दुनिया के लगभग 15 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के साथ आसान कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। यात्रियों के लिए अहमदाबाद में ही बैगेज चेकिंग और इमिग्रेशन जैसी प्रक्रियाएं पूरी करने की सुविधा मिलने से उन्हें दिल्ली में फ्लाइट बदलते समय होने वाली परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अंतरराष्ट्रीय यात्रा और भी निर्बाध हो जाएगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या आज बढ़कर 160 से अधिक हो गई है। अगले दस वर्षों में 'उड़ान' योजना के विस्तार के साथ देश में 100 और एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र देश की आर्थिक गति, रोजगार और व्यापार-उद्योग के विकास का अहम माध्यम बन रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि अहमदाबाद की बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी से हॉस्पिटैलिटी, पर्यटन, टेक्सटाइल, फार्मास्युटिकल, डायमंड-जेम्स, इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 'उड़ान यात्री कैफे', एयरपोर्ट लाइब्रेरी और डिजिटल बोर्डिंग पास जैसी पहलों के जरिए यात्रियों की सुविधा और अनुभव को और बेहतर बनाया जा रहा है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' विजन के तहत देश का एविएशन सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर और एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) क्षेत्र में हुए नीतिगत सुधारों से भारत तेजी से ग्लोबल एविएशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी समय में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को अधिक मजबूत बनाकर नए एयरपोर्ट और डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि दुनियाभर में फैला विशाल प्रवासी गुजराती समुदाय, गुजरात का मजबूत व्यापारिक आधार और पर्यटन की अपार संभावनाओं के कारण अहमदाबाद वैश्विक संपर्क का एक मुख्य केंद्र बनेगा।

नागरिक उड्डयन सचिव श्री समीर सिन्हा ने स्वागत भाषण में कहा कि वाराणसी और अमृतसर की सफलता के बाद, अहमदाबाद के इस नेटवर्क में शामिल होने से देश में सीमलेस कनेक्टिविटी का एक नया युग शुरू हुआ है। 'हब एंड स्पोक' मॉडल केवल एक नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सशक्त ढांचा है, जो यात्रियों, एयरलाइंस और एयरपोर्ट, सभी के लिए फायदेमंद है। इस व्यवस्था से यात्री अहमदाबाद से ही देश के मुख्य हब के जरिए दुनिया के किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि 'हब एंड स्पोक' एक एयरलाइन ऑपरेशनल सिस्टम है, जिसके तहत छोटे शहरों (स्पोक) के यात्रियों को बड़े केंद्रीय एयरपोर्ट (हब) पर लाया जाता है, और वहां से उन्हें कनेक्टिंग अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट में भेजा जाता है। इस सुविधा से यात्रियों के सामान, कस्टम और इमिग्रेशन से संबंधित सभी जांच शुरुआती एयरपोर्ट पर ही पूरी हो जाएंगी, जिससे हब एयरपोर्ट पर दोबारा सुरक्षा जांच या चेक-इन करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वचालित सामान ट्रांसफर और आसान प्रक्रिया से यात्रियों के समय की बचत होगी और एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च में कमी आएगी।

उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी, अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास, अदानी एयरपोर्ट के निदेशक श्री जीत अदानी, एयर इंडिया ग्रुप के कॉर्पोरेट अफेयर्स के प्रमुख श्री पी. बालाजी, पर्यटन सचिव श्री कुलदीप आर्य, नागरिक उड्डयन विभाग के पदाधिकारी, एयर इंडिया और अदानी एयरपोर्ट के प्रतिनिधियों सहित आमंत्रित महानुभाव मौजूद रहे।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

चलती बस में चालक परिचालक द्वारा यौन हिंसा

एक बार फिर बारह साल पुराने निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। निर्भयाकांड में दिसंबर 2012 में 23 साल की युवती के साथ क्रूरता से गैंगरेप हुआ था, जिसकी बाद में सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद देश में व्यापक आक्रोश उभरा था। यौन हिंसा के खिलाफ कानून कठोर किए गए। इस कांड में साल 2020 में चार अपराधियों को फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्त कानून और कठोर सजाओं के बाद ऐसे अपराधों पर अंकुश लगा? दुखद है कि एक बार फिर निर्भयाकांड की पुनरावृत्ति हुई । अकेली नाबालिग लड़की, खाली बस और चलती बस में चालक-परिचालक द्वारा गैंग रेप। उ.प्र. की एक सोलह साल की लड़की किसी बात पर मां की डांट से क्षुब्ध हो घर छोड़कर अपने रिश्तेदार से मिलने नोयडा सेक्टर-63 के लिये चली। लेकिन रात के अंधेरे और बारिश के मौसम की गफलत में नोयडा के परी चौक पर उतर गई। सेक्टर-63 जाने के लिये उसने जिस बस को रुकवाया, उसमें बैठे दरिंदों ने बस के वहीं जाने की बात कहकर उसे बैठा लिया। पर्दे लगी स्लीपर बस में लड़की के बैठते ही परिचालक ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। चालक-परिचालक ने दुराचार किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। करीब 47 किलोमीटर के सफर में उसके साथ यौन हिंसा हुई। अपराधी उसे कश्मीरी गेट के निकट रिंग रोड में छोड़कर फरार हो गए। किशोरी ने साहस दिखाते हुए रात ही में कश्मीरी गेट पुलिस को वारदात की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में टीम बनाकर पड़ताल की। बस की पहचान व रूट की जानकारी सीसीटीवी कैमरों के जरिये की गई। चालक-परिचालक को तिमारपुर की बस पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। फोरेंसिक जांच के लिये बस को भी कब्जे में लिया गया है। लेकिन सवाल है कि चार अगस्त की घटना को पुलिस ने क्यों पर्दे में रखा? आखिर क्यों हादसे की सार्वजनिक जानकारी 31 अगस्त को मीडिया को दी गई?

वहीं दूसरी ओर इंसान के पतन की पराकाष्ठा दिल्ली के बवाना इलाके में सामने आई, जहां स्कूल बस चालक को नर्सरी की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने पर गिरफ्तार किया गया है। घटना 19 अगस्त को सामने आई जब नर्सरी की छात्रा के परिजनों ने उसके निजी अंगों पर चोट के निशान देखे। बच्ची ने अपनी मां को स्कूल के एक गंदे अंकल के बारे में बताया जो उसे चॉकलेट देता था। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचित करने के बाद बस चालक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार बच्ची से चार बार यौन दुर्व्यवहार किया गया था। किसी सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं जहां समाज में भरोसे को तोड़ती हैं, वहीं कानून व्यवस्था के प्रश्न को भी उठाती हैं। इन मुद्दों पर राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार में दिल्ली रेप कैपिटल बनती जा रही है। इसके बावजूद कि दिल्ली में एक महिला मुख्यमंत्री हैं। वहीं कुछ राजनीतिक दल आरोप लगा रहे हैं कि जनता की सुरक्षा व अपराध रोकने के कार्य के बजाय पुलिस पर अन्य कार्यों का बोझ डाला जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि पुलिस ने मामले की तह तक जाकर अपराधियों को समय रहते गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई में तेजी दिखायी है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वे जागरूक रहें और ऐसी घटनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि भारत में यौन लिप्साओं के विस्फोट की असली वजह क्या है? क्यों किन्हीं कमजोर स्थितियों में महिला, लड़की व बच्ची की उम्र का भी लिहाज न कर, यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है? हमारा समाज पतनोन्मुखी क्यों होता जा रहा है? क्या यौन अपराधों के मूल में मोबाइल में इंटरनेट के जरिये परोसी जा रही यौन उत्तेजक सामग्री है? देश के समाज विज्ञानियों को इस गंभीर प्रश्न पर मंथन करना होगा।

मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा: भारतीय चिंतन की सार्थक प्रस्तुति

> "मोहन भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित हैं। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की अगस्त 2026 की अमेरिका यात्रा को केवल प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम तक सीमित करके देखना उसके व्यापक अर्थ को छोटा करना होगा। न्यूयार्क में 29 अगस्त को आयोजित 'एक विश्व, एक मानवता' कार्यक्रम में उनका संबोधन ऐसे समय हुआ, जब संघ को लेकर भारत ही नहीं, विदेशों में भी अनेक धारणाएं, आरोप और पूर्वाग्रह सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे वातावरण में भागवत ने जिस प्रकार विविधता, संवाद, सेवा, सह-अस्तित्व और मानवीय एकात्मता को केंद्र में रखा, उसने संघ की विचारधारा को उसके समर्थकों के लिए ही नहीं, बल्कि वैश्विक समाज के सामने भी एक अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया। यह यात्रा इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और उसके विचार अब भारत की सीमाओं से बाहर भी व्यापक चर्चा का विषय बन रहे हैं। भागवत का अमेरिका जाना वस्तुतः संघ के विचार को प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से समझाने का अवसर बना। संघ के बारे में भारत में लंबे समय से दो विपरीत धारणाएं दिखाई देती रही हैं। एक पक्ष उसे भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभावना, सेवा और सामाजिक संगठन की विराट शक्ति मानता है, जबकि दूसरा पक्ष उसके विचारों को संकीर्ण धार्मिक राजनीति से जोड़कर देखता है। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने समय-समय पर संघ और उसके विचारों पर गंभीर राजनीतिक प्रश्न उठाए हैं। अमेरिका में भी कार्यक्रम से पहले कुछ संगठनों और राजनीतिक व्यक्तियों ने भागवत की यात्रा और संघ की विचारधारा पर आपत्तियां व्यक्त कीं। ऐसे माहौल में किसी संस्था की वास्तविक छवि केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं बनती, वह संवाद से बनती है। यही इस यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। भागवत ने अपने विचार विरोधियों पर आक्रमण करके नहीं, बल्कि भारतीय चिंतन की व्याख्या करके सामने रखे। इससे संघ को लेकर बनी धारणाओं पर बहस का एक नया आधार तैयार हुआ।न्यूयार्क में भागवत के वक्तव्य का सबसे अधिक चर्चित पक्ष उनका हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर स्पष्ट कथन रहा। उन्होंने कहा कि यदि कोई हिंदू यह मानता है कि भारत में मुसलमानों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए, तो वह हिंदू नहीं रह सकता। यह कथन राजनीतिक नारे से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें हिंदुत्व की उनकी व्याख्या को सामाजिक समावेश के साथ जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि सत्य एक है और उसे समझने तथा व्यक्त करने के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं। भारतीय परंपरा की यही विशेषता है कि वह मतभिन्नता को अस्तित्व के संकट के रूप में नहीं, बल्कि सत्य की विविध अभिव्यक्तियों के रूप में देखने की क्षमता रखती है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है-यदि हिंदुत्व का अर्थ भारत की सांस्कृतिक चेतना है, तो क्या वह किसी समुदाय को भारत से बाहर कर सकता है? भागवत का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक दिखाई देता है। उनका कथन हिंदुत्व की उस व्याख्या को सामने रखता है, जिसमें भारतीयता किसी एक पूजा-पद्धति की बपौती नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक विरासत है।

भागवत ने अमेरिका में भारत की विविधता को उसकी कमजोरी नहीं, शक्ति बताया। उनके अनुसार विविधता और एकता भारत के स्वभाव में ही अंतर्निहित हैं। भारत में भाषा, जाति, पंथ, पूजा-पद्धति और परंपराओं की असंख्य धाराएं हैं, फिर भी इन्हें एक साझा सभ्यतागत चेतना जोड़ती रही है। यह संदेश आज के विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अनेक देशों में धार्मिक पहचान, नस्लीय भेद, सांस्कृतिक असहमति और राजनीतिक ध्रुवीकरण सामाजिक तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे समय भारत का अनुभव यह बताता है कि भिन्नताओं को मिटाना आवश्यक नहीं, उन्हें सम्मान देकर भी एकता स्थापित की जा सकती है। यही विचार भागवत के संबोधन को सामान्य राजनीतिक भाषण से ऊपर उठाता है। उनका आग्रह था कि विविधता को स्वीकार ही नहीं, सम्मान और संरक्षण भी मिलना चाहिए। संघ की सार्वजनिक छवि का एक बड़ा हिस्सा राजनीतिक विमर्श से निर्मित हुआ है, जबकि संघ स्वयं को सामाजिक संगठन और सेवा-आधारित सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। भागवत ने अमेरिका में भी सेवा, सामाजिक समरसता और संवाद को परिवर्तन का आधार बताया। यही वह बिंदु है जहां संघ की छवि को केवल चुनावी राजनीति के चश्मे से देखने की सीमा सामने आती है। किसी संगठन को समझने के लिए उसके राजनीतिक प्रभाव के साथ उसकी सामाजिक गतिविधियों, सेवा-कार्य, संगठनात्मक संस्कृति और वैचारिक आधार को भी देखना आवश्यक है। भागवत की यात्रा ने कम से कम इतना अवसर अवश्य दिया कि संघ को उसके अपने शब्दों और उसके सरसंघचालक की प्रत्यक्ष व्याख्या के आधार पर सुना जाए।

अमेरिका में बसे भारतीयों से भागवत ने एक संतुलित संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस देश में वे रह रहे हैं, वह उनकी कर्मभूमि है और वहां के प्रति उनकी निष्ठा तथा दायित्व सर्वोपरि हैं। साथ ही भारत उनकी जन्मभूमि है, जिससे उन्हें मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक संस्कारों की विरासत मिली है। यह दृष्टि प्रवासी भारतीयों के सामने पहचान के संघर्ष के बजाय पहचान के समन्वय का मार्ग रखती है। अपनी जड़ों से जुड़े रहना और जिस समाज में रह रहे हैं उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखना-दोनों एक साथ संभव हैं। यही भारतीय संस्कृति की उदारता है। यह भी तथ्य है कि भागवत के कार्यक्रम का अमेरिका में विरोध हुआ और संघ की विचारधारा को लेकर तीखी आलोचनाएं सामने आईं। लेकिन लोकतांत्रिक समाज में किसी विचार का उत्तर उसे दबाकर नहीं, उसके साथ संवाद करके दिया जाता है। इस दृष्टि से यह यात्रा संघ के लिए भी एक परीक्षा थी। भागवत ने विरोध का उत्तर आक्रामक भाषा में देने के बजाय एकात्मता, मानवता और सह-अस्तित्व की बात की। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। आलोचक उनके शब्दों और संघ के व्यवहार के बीच अंतर का प्रश्न उठा रहे हैं, समर्थक इसे संघ के मूल विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मान रहे हैं। इस बहस का अंतिम निर्णय समय और व्यवहार करेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि बहस अब अधिक प्रत्यक्ष और वैश्विक हो गई है।

मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा को संघ की छवि पर वर्षों से चले आ रहे विवाद का अंतिम उत्तर मानना अतिशयोक्ति होगी। किंतु इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ अवश्य कहा जा सकता है। जिन लोगों ने संघ को केवल राजनीतिक आरोपों और विरोधी व्याख्याओं के माध्यम से जाना है, उन्हें पहली बार इतने बड़े वैश्विक मंच पर उसके शीर्ष नेतृत्व की विचार-दृष्टि को सीधे सुनने का अवसर मिला। यह यात्रा संघ के लिए एक उजाला इसलिए बनी है कि इसमें प्रतिरक्षा की भाषा कम और आत्मविश्वास की भाषा अधिक दिखाई दी। इसमें यह कहने का प्रयास था कि भारतीयता किसी के निषेध से नहीं, सबके सम्मान से मजबूत होती है, हिंदुत्व किसी समुदाय के बहिष्कार से नहीं, मानवता की एकात्म दृष्टि से सार्थक होता है और भारत की शक्ति उसकी समानता में नहीं, उसकी विविधताओं के बीच बनी रहने वाली सांस्कृतिक एकता में है।

आज विश्व को केवल आर्थिक शक्ति, सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसा जीवन-दर्शन भी चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ सके। भागवत के अमेरिकी संबोधन में भारत की इसी भूमिका की कल्पना दिखाई दी-एक ऐसा भारत जो अपनी परंपरा के बल पर विश्व को सह-अस्तित्व, संवाद और एकात्मता का रास्ता दिखा सके। मोहन भागवत की यह यात्रा इसलिए स्मरणीय रहेगी कि उसने संघ के बारे में चल रही बहस को भारत की सीमाओं से निकालकर विश्व के सार्वजनिक विमर्श में पहुंचा दिया। अब संघ की पहचान केवल उसके विरोधियों के आरोपों या समर्थकों के दावों से नहीं, बल्कि उसके विचार, उसके व्यवहार और समाज के साथ उसके संवाद से तय होगी। अंततः किसी विचारधारा की सबसे बड़ी शक्ति उसका प्रचार नहीं, उसका आचरण होता है। अमेरिका की धरती से भागवत ने जो संदेश दिया है, उसकी वास्तविक कसौटी भारत की धरती पर सामाजिक समरसता, सेवा, संवाद और सह-अस्तित्व के रूप में दिखाई देगी। यदि यह संदेश व्यवहार में उतरता है, तो यह केवल संघ की छवि को नहीं, भारत की वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई दे सकता है।

प्रेरणा

ऋतु शर्मा की गीता साधना ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, अमृतसर की बेटी ने सेवा को बनाया जीवन का धर्म

अमृतसर की ऐतिहासिक धरती से निकली ऋतु शर्मा ने आध्यात्मिक साधना और समाजसेवा के क्षेत्र में ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो पूरे पंजाब के लिए गर्व का विषय बन गया है। श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय के सामूहिक उच्चारण में शामिल होकर ऋतु शर्मा ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस उपलब्धि ने उनके माता-पिता, गीता परिवार पंजाब और अमृतसर का गौरव बढ़ाया है। खास बात यह है कि ऋतु ने इस सफलता को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे भारतीय संस्कृति, सनातन ज्ञान और सेवा की भावना से जोड़कर आगे बढ़ने का माध्यम बनाया है।

ऋतु शर्मा का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो मानते हैं कि सफलता केवल धन, पद या करियर में आगे बढ़ने का नाम नहीं है। जीवन को किसी सार्थक उद्देश्य के लिए समर्पित करना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। ऋतु ने अपने जीवन में इसी विचार को अपनाया। उन्होंने एक ओर श्रीमद्भगवद्गीता के अध्ययन और साधना को अपनाया तो दूसरी ओर जरूरतमंदों की सेवा को अपना कर्म बनाया। यही कारण है कि उनका नाम केवल एक विश्व रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि सेवा और संस्कार की एक लंबी यात्रा से जुड़ा हुआ है।

गीता परिवार और चिन्मय मिशन की ओर से आयोजित विशाल ऑनलाइन कार्यक्रम में दुनिया के लगभग 70 देशों से 75 हजार से अधिक साधकों ने श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय के सामूहिक चैंटिंग के लिए पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 8 हजार साधकों को पुरुषोत्तम योग का उच्चारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऋतु शर्मा भी इस ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बनीं। हजारों साधकों के साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हुए उन्होंने उस आध्यात्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला।

इस उपलब्धि की नींव हालांकि बहुत पहले पड़ चुकी थी। ऋतु को श्रीमद्भगवद्गीता के प्रति रुचि अपने माता-पिता से मिले संस्कारों के कारण हुई। उनके परिवार में आध्यात्मिक जीवन और भारतीय संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाता था। माता-पिता के जीवन और उनके धार्मिक संस्कारों ने ऋतु के मन में भी गीता को जानने की इच्छा पैदा की। बचपन में सुने गए धार्मिक और राष्ट्रभक्ति से जुड़े प्रसंग धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनते गए। आगे चलकर इन्हीं संस्कारों ने उन्हें आध्यात्मिक साधना और समाजसेवा के रास्ते पर आगे बढ़ाया।

वर्ष 2023 में ऋतु शर्मा गीता परिवार से जुड़ीं। गीता परिवार का उद्देश्य दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों का सही उच्चारण सिखाना और उन्हें कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करना है। ऋतु ने यहां से मिलने वाली शिक्षा को पूरी निष्ठा के साथ अपनाया। उन्होंने नियमित अभ्यास किया और गीता के श्लोकों को याद करने के साथ उनके भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उनकी मेहनत का परिणाम दिसंबर 2024 में सामने आया, जब उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ करने की 'गीताव्रती' परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। इसके साथ ही वह अमृतसर की पहली गीताव्रती बनने का गौरव हासिल करने में सफल रहीं। इसके बाद उन्होंने साधना को और आगे बढ़ाया। मई 2025 में उन्होंने 'गीता विचक्षण आरोही' और अगस्त 2025 में 'गीता विचक्षण अवरोही' की परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी की। लगातार बढ़ती यह उपलब्धियां उनके अनुशासन और समर्पण को दर्शाती हैं।

ऋतु को गीता परिवार की ओर से आयोजित 'गीता कंठनाद' कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिला। उनके लिए यह अनुभव केवल किसी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं था, बल्कि गीता के प्रति उनकी साधना को और गहरा करने वाला अवसर था। वर्तमान में भी वह समाजसेवा के साथ गीता परिवार की आध्यात्मिक गतिविधियों में अपना योगदान दे रही हैं। उनके लिए गीता जीवन जीने की दिशा दिखाने वाला ग्रंथ है, जिसका ज्ञान केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

ऋतु शर्मा के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष उनकी राष्ट्र और समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। बचपन से ही उन्होंने देश के महानायकों के त्याग और बलिदान की कहानियां सुनीं। इन प्रसंगों ने उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की इच्छा पैदा की। जब करियर चुनने का समय आया तो उन्होंने व्यक्तिगत सफलता की राह के बजाय समाजसेवा को प्राथमिकता दी। यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन परिवार ने उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से पूरा सहयोग दिया।

उन्होंने जरूरतमंद बच्चों को आश्रम में निःशुल्क पढ़ाने से अपनी सेवा यात्रा शुरू की। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का यह प्रयास धीरे-धीरे व्यापक सेवा कार्य में बदल गया। वह ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा चैरिटेबल सोसाइटी से जुड़ीं और वहां पूर्णकालिक रूप से सेवा कार्य करने लगीं। कम उम्र में सेवा शुरू करने वाली ऋतु ने अपने कार्य और समर्पण से यह साबित किया कि समाज को बदलने के लिए बड़े पद की नहीं, बड़े हृदय की जरूरत होती है।

आज ऋतु शर्मा का जीवन गीता के ज्ञान और मानव सेवा के अद्भुत मेल का उदाहरण बन चुका है। उनके लिए आध्यात्मिकता केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक अर्थ जरूरतमंदों के जीवन में सहारा बनना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। गीता साधना ने उन्हें आत्मअनुशासन दिया और समाजसेवा ने उस ज्ञान को कर्म में बदलने का अवसर दिया।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज होना निश्चित रूप से गौरव का विषय है, लेकिन ऋतु की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा और समय को समाज के लिए समर्पित किया। उनकी यात्रा आज की युवा पीढ़ी को यह संदेश देती है कि जीवन में सफलता पाने के साथ-साथ उसे सार्थक बनाना भी जरूरी है। अमृतसर की इस बेटी ने गीता के श्लोकों से विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अपने सेवा भाव से लोगों के दिलों में जो स्थान बनाया है, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है।

क्या विस्तार के बाद Global Economy की दिशा बदल पाएगा भारत? 11 देशों के Leaders पर टिकी नजरें

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली का भारत मंडपम 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। वर्ष 2006 में बने इस समूह के 20 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित यह बैठक बेहद अहम है। दुनिया की 45 प्रतिशत से ज्यादा आबादी और करीब 30 फीसदी वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला यह मंच आज एक ताकतवर गुट बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेंगे, तो भारत के सामने कई कूटनीतिक चुनौतियां होंगी। बदलते वैश्विक व्यापार नियमों और पश्चिम एशिया के संकट के बीच नई दिल्ली के लिए यह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने, 'ग्लोबल साउथ' की आवाज बनने और ब्रिक्स को पश्चिमी-विरोधी धड़े में तब्दील होने से बचाने का एक बड़ा इम्तिहान होगा।भारत ने इस साल 1 जनवरी को ब्राज़ील से ब्रिक्स की बारी-बारी से मिलने वाली अध्यक्षता औपचारिक रूप से संभाली। अध्यक्षता की आधिकारिक थीम - मज़बूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण से प्रेरित होकर, नई दिल्ली ने अपनी अध्यक्षता को "मानवता सर्वोपरि" की भावना पर आधारित, इंसान-केंद्रित नज़रिए के इर्द-गिर्द तैयार किया है। नेताओं का यह दो-दिन का शिखर सम्मेलन, साल भर चले एक बड़े डिप्लोमैटिक अभियान का नतीजा है। भारत की अध्यक्षता में, देश भर के 25 शहरों में 350 से ज़्यादा मंत्री-स्तरीय, वर्किंग-ग्रुप और ट्रैक-टू बैठकें हुईं। इन तैयारियों में तीन मुख्य पहलू शामिल थेः राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय गवर्नेंस, और सांस्कृतिक व लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान। इनसे पहले हुई अहम बैठकों में मई में नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और अगस्त में पुणे में ब्रिक्स इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ (ICT) ट्रैक की बैठक शामिल हैं। नई दिल्ली का यह शिखर सम्मेलन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह इस ग्रुप के औपचारिक रूप से ब्रिक्स+ में विस्तार के बाद नेताओं का पहला पूर्ण-स्तरीय शिखर सम्मेलन है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका जैसे संस्थापक सदस्यों के अलावा, अब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी इसके सदस्य बन गए हैं। सम्मेलन के विस्तारित सत्रों में कई आमंत्रित सदस्य और क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे जिनमें BIMSTEC, ASEAN, अफ़्रीकी संघ और खाड़ी सहयोग परिषद के नेता शामिल हैं। सरकारीसेवाएं खोजना

जब भारतीय राजनयिक शिखर सम्मेलन के घोषणा-पत्र को अंतिम रूप दे रहे हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वैचारिक है। 11 सदस्यों वाले इस बड़े समूह में इस बात को लेकर बुनियादी मतभेद हैं कि ब्रिक्स को कैसा होना चाहिए। मॉस्को और बीजिंग ब्रिक्स को पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने, G7 के प्रभुत्व का मुकाबला करने और पश्चिमी प्रभाव से मुक्त एक वैकल्पिक आर्थिक ढांचा तैयार करने के लिए एक मुख्य भू-राजनीतिक साधन के रूप में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगातार इस बात पर ज़ोर देते रहे हैं कि इस समूह में पश्चिमी प्रतिबंधों और सुरक्षा गठबंधनों का मुकाबला करने की क्षमता है। इसके विपरीत, भारत इस बात को नहीं मानता कि ब्रिक्स को पश्चिमी-विरोधी टकराव वाले गठबंधन के तौर पर काम करना चाहिए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बार-बार नई दिल्ली का रुख स्पष्ट किया हैः ब्रिक्स गैर-पश्चिमी है, पश्चिमी-विरोधी नहीं। भारत का रणनीतिक हित इस बात में है कि वह ब्रिक्स (BRICS) का इस्तेमाल मौजूदा ग्लोबल संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक — में सुधार लाने के लिए करे, न कि उन्हें खत्म करके ध्रुवीकृत और कोल्ड-वॉर जैसे गुटों में बंटी दुनिया बनाए। संतुलन बनाने की इस कोशिश में भारत की एक खास स्थिति हैः वह अकेला ऐसा देश है जो ब्रिक्स और क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad) जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं दोनों का सक्रिय सदस्य है। एक तरफ भारत इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और डिफेंस सप्लाई चेन के मामलों में वॉशिंगटन और यूरोप की राजधानियों के साथ मिलकर काम करता है, तो दूसरी तरफ वह नई दिल्ली में रूस, चीन और ईरान के साथ भी एक ही मेज पर बैठता है।

इस समिट की मेज़बानी करने के लिए नई दिल्ली को दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ जटिल द्विपक्षीय मतभेदों को संभालना होगा और साथ ही बहुपक्षीय नतीजों की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा।

सैन्य बातचीत के बाद 'लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) पर धीरे-धीरे सेना पीछे हटने के बावजूद, भारत और चीन के बीच बुनियादी तनाव अभी भी बना हुआ है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा, सीमा सुरक्षा और दक्षिण एशिया में बीजिंग का बढ़ता प्रभाव, दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। ब्रिक्स (BRICS) के संदर्भ में, भारत इस बात को लेकर सतर्क है कि चीन इस बड़े हुए समूह का इस्तेमाल अपनी क्षेत्रीय पहलों को आगे बढ़ाने या ब्रिक्स को बीजिंग की विदेश नीति के लक्ष्यों का समर्थन करने वाला मंच बनाने के लिए न करे।

अभियान

कृष्ण भक्ति में डूबना है तो जरूर करें इन 10 दिव्य धामों के दर्शन, हर मंदिर की अपनी अनोखी महिमा

भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेते ही मन में प्रेम, करुणा, भक्ति, शांति और दिव्यता का भाव जाग उठता है। भगवान विष्णु के पूर्णावतार माने जाने वाले श्रीकृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना के साथ-साथ प्रेम, कर्म और सत्य का संदेश दिया। यही कारण है कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भगवान श्रीकृष्ण के करोड़ों भक्त हैं। भारत में तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जहां कृष्ण भक्ति से जुड़ा कोई मंदिर, धाम या धार्मिक स्थल न हो। इन मंदिरों में वर्षभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और विशेष अवसरों पर यहां भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए सबसे विशेष पर्वों में से एक है। वर्ष 2026 में जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर देशभर के कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन, झांकियां और धार्मिक आयोजन होंगे। आधी रात को भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाएगा और मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाएगा। अगर आप इस जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो देश के कुछ ऐसे धाम हैं, जहां जाना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है।

पुरी का जगन्नाथ मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में शामिल है। धार्मिक मान्यताओं में पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्रीकृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। ओडिशा के पुरी में स्थित यह मंदिर चार धामों में शामिल है और सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। मंदिर की परंपराएं और यहां होने वाली रथयात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पुरी का विशाल मंदिर परिसर अपनी स्थापत्य कला और धार्मिक परंपराओं के कारण भी विशेष महत्व रखता है। जन्माष्टमी के दौरान भी यहां भक्तिभाव का अद्भुत वातावरण देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश का वृंदावन भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और राधा-कृष्ण की प्रेम भक्ति से जुड़ा हुआ है। यहां स्थित प्रेम मंदिर आधुनिक समय में कृष्ण भक्ति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। सफेद संगमरमर से बना यह मंदिर अपनी भव्यता और सुंदर नक्काशी के लिए जाना जाता है। मंदिर परिसर में भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की विभिन्न लीलाओं को दर्शाती सुंदर झांकियां दिखाई देती हैं। रात के समय रंग-बिरंगी रोशनी से मंदिर का दृश्य बेहद आकर्षक हो जाता है। विशेष पर्वों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। प्रेम मंदिर में पहुंचकर भक्तों को भक्ति, सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

वृंदावन का कृष्ण-बलराम मंदिर, जिसे आमतौर पर इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर राधा-कृष्ण और कृष्ण-बलराम की भक्ति के लिए जाना जाता है। यहां सुबह से लेकर रात तक भजन, कीर्तन और आध्यात्मिक गतिविधियां चलती रहती हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अक्सर सामूहिक कीर्तन में झूमते हुए भगवान का नाम लेते दिखाई देते हैं। देश-विदेश से बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त यहां पहुंचते हैं। मंदिर की स्थापना 1970 के दशक में हुई और इसके बाद यह वृंदावन आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी प्रमुख आकर्षण बन गया। जन्माष्टमी के अवसर पर यहां विशेष उत्सव का आयोजन होता है और पूरा परिसर कृष्ण नाम के जयघोष से गूंज उठता है। मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर भी भगवान श्रीकृष्ण की नगरी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मथुरा को भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है और इस कारण यहां के प्रत्येक धार्मिक स्थल का अपना विशेष महत्व है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण का सुंदर श्रृंगार किया जाता है और विभिन्न अवसरों पर विशेष आरती तथा पूजा होती है। मंदिर के आसपास यमुना नदी के पवित्र घाट हैं, जहां श्रद्धालु स्नान, पूजा और आराधना करते हैं। शाम के समय यमुना आरती का वातावरण श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रूप से अभिभूत कर देता है। जन्माष्टमी के दौरान मथुरा-वृंदावन का पूरा क्षेत्र कृष्णमय हो जाता है। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्रीनाथजी मंदिर कृष्ण भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धाम है। यहां भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप श्रीनाथजी की पूजा की जाती है। श्रीनाथजी को गोवर्धनधारी कृष्ण के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार श्रीनाथजी की प्रतिमा को मुगल काल में गोवर्धन क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर लाया गया था और बाद में नाथद्वारा में प्रतिष्ठित किया गया। मंदिर में भगवान का दिन में कई बार श्रृंगार और भोग होता है। यहां की पूजा पद्धति और सेवा परंपरा बेहद विशिष्ट मानी जाती है। देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रीनाथजी के दर्शन के लिए नाथद्वारा पहुंचते हैं।

दक्षिण भारत में भी भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर इसी का उदाहरण है। पहाड़ी पर स्थित यह भव्य मंदिर धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ स्थापत्य कला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां भगवान श्रीकृष्ण और राधारानी की पूजा होती है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं और बुजुर्गों तथा दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। मंदिर का उद्देश्य वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाना है। यहां होने वाले भजन-कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम भक्तों को आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करते हैं। गुजरात के खेड़ा जिले में स्थित डाकोर का श्री रणछोड़रायजी मंदिर भी भगवान श्रीकृष्ण के प्रमुख धामों में गिना जाता है। यहां भगवान कृष्ण को रणछोड़राय के नाम से पूजा जाता है। डाकोर में भगवान रणछोड़राय का भव्य मंदिर गोमती तालाब के निकट स्थित है। मंदिर की स्थापत्य शैली और धार्मिक परंपराएं श्रद्धालुओं को आकर्षित करती हैं। यहां भगवान के दर्शन के लिए दूर-दूर से भक्त पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं में डाकोर को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने वाले पवित्र स्थलों में माना जाता है। विशेष पर्वों पर मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में रंग जाता है।

तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित अरुलमिगु श्री पार्थसारथी स्वामी मंदिर दक्षिण भारत की प्राचीन वैष्णव परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। भगवान श्रीकृष्ण यहां पार्थसारथी के रूप में पूजे जाते हैं। महाभारत में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और इसी स्वरूप की स्मृति इस मंदिर से जुड़ी है। मंदिर की स्थापना प्राचीन काल से मानी जाती है और इसकी वास्तुकला दक्षिण भारतीय मंदिर परंपरा की विशिष्ट झलक प्रस्तुत करती है। मंदिर में भगवान विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की भी पूजा की जाती है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यह मंदिर कृष्ण भक्तों के साथ-साथ दक्षिण भारत की वैष्णव परंपरा को समझने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है।

कर्नाटक के ऐतिहासिक नगर हम्पी में स्थित बालकृष्ण मंदिर भी भगवान श्रीकृष्ण के अद्भुत मंदिरों में शामिल है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा यह मंदिर अपनी स्थापत्य कला और विशाल संरचना के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी के ऐतिहासिक स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिला हुआ है। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर की गई कलात्मक नक्काशी उस समय की स्थापत्य प्रतिभा की कहानी कहती है। यहां पहुंचकर भक्तों को आध्यात्मिकता के साथ भारतीय इतिहास और वास्तुकला की समृद्ध विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलता है।

कर्नाटक का उडुपी श्रीकृष्ण मठ भी भगवान श्रीकृष्ण के सबसे प्रसिद्ध धामों में से एक है। उडुपी की कृष्ण भक्ति परंपरा का संबंध संत माध्वाचार्य से जोड़ा जाता है। यहां भगवान श्रीकृष्ण की पूजा एक विशेष परंपरा के अनुसार की जाती है। मंदिर में भगवान के दर्शन एक विशेष खिड़की से करने की परंपरा है, जिसे कनकन किंडी कहा जाता है। इसके पीछे संत कनकदास से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक कथा सुनाई जाती है। मंदिर परिसर के आसपास प्राचीन मठ और धार्मिक संस्थान भी हैं। यहां का आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। इन दस मंदिरों की विशेषता केवल इनकी भव्यता या प्राचीनता नहीं है, बल्कि इनसे जुड़ी आस्था, परंपरा और कृष्ण भक्ति की अलग-अलग धाराएं हैं। कहीं भगवान बाल गोपाल के रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं रणछोड़राय, पार्थसारथी, जगन्नाथ या श्रीनाथजी के रूप में। हर धाम की अपनी पूजा पद्धति, अपनी मान्यता और अपनी धार्मिक परंपरा है। यही विविधता भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। जन्माष्टमी के अवसर पर इन मंदिरों में दर्शन करना भक्तों के लिए विशेष अनुभव हो सकता है। हालांकि किसी भी मंदिर के बारे में यह निश्चित रूप से कहना उचित नहीं है कि केवल दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाएगी।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

पंचायती राज को अधिक सशक्त बनाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से एक दिवसीय 'पंचायत संस्कार कार्यशाला' का शुभारंभ : विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की विशेष उपस्थिति

▸▸ विकास कार्यों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं; जन प्रतिनिधि जनता की समस्याएँ सुनें, नियमों को समझें और गुणवत्तापूर्ण कार्य करें : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ मुख्यमंत्री का गरीब तथा अंतिम छोर के व्यक्ति तक सभी सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ पहुँचाने का आह्वान

▸▸ पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों को निरंतर सीखने तथा नियमों की मर्यादा में रहकर जन कल्याण के कार्य करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए : विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी

▸▸ लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अधिकार एवं कर्तव्य; दोनों को समझकर पंचायत व्यवस्था अधिक मजबूत की जा सकेगी : विधानसभा अध्यक्ष

▸▸ 'समृद्ध गाँव से विकसित राष्ट्र' के संकल्प के साथ ग्रामीण विकास को मिली नई गति : ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया

गांधीनगर : गांधीनगर स्थित गुजरात विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से मंगलवार को नवनियुक्त पंचायत पदाधिकारियों के लिए एक दिवसीय 'पंचायत संस्कार कार्यशाला' का शुभारंभ किया गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी की विशेष उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में त्रिस्तरीय पंचायती राज के 70 महिला प्रतिनिधियों सहित कुल 188 पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गुजरात विधानसभा सचिवालय के गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं तथा विकासोन्मुखी कार्यों का लाभ समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के लिए पंचायत पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था। इस अवसर पर महानुभावों ने पदाधिकारियों को प्रेरणादायी मार्गदर्शन देकर लोकहित तथा ग्रामीण विकास के लिए अधिक सक्रियता से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गाँवों से लेकर राज्य स्तर तक सभी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए धन या बजट की कोई कमी नहीं है। श्री पटेल ने पंचायत के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यदि उनके पास उचित आयोजन, नियमों की सही समझ और कार्य करने की दृढ़ इच्छाशक्ति हो; तो सरकार उन्हें आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 1995 से अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव शेयर करते हुए कहा, "जन प्रतिनिधियों के पास जब नागरिक अपनी समस्याएँ लेकर आएँ, तब उन्हें पर्याप्त समय देकर सुनना अत्यंत आवश्यक है। आवेदक को सीधे अधिकारी के पास भेज देने या बात टालने के बजाय स्वयं सही तथ्य समझकर, नियमों की जानकारी प्राप्त कर अधिकारी के साथ चर्चा करेंगे, तो प्रत्येक जटिल समस्या का सरल रास्ता निकलेगा।"

मुख्यमंत्री ने सचेत किया कि गाँवों में निर्मित होने वाले सड़क मार्ग, विद्यालय और पंचायत भवन जैसे विकास कार्य दीर्घकालीन एवं उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए। नए विकास कार्य लंबे समय तक टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण बनें, तो जन प्रतिनिधि तथा सरकार; दोनों के प्रति जनता का विश्वास दोगुना होता है। इसलिए, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कार्य की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना केवल टिकाऊ और श्रेष्ठ कार्य ही हों। 'नल से जल' और आवास योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत में पदाधिकारी या पार्टी बदल जाए, फिर भी जनहित के सभी कार्यों को निरंतर गति से पूरा करना वर्तमान पदाधिकारियों का कर्तव्य है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में अनियमितता या गलती हुई हो, तो उसकी कानूनी जाँच भले ही समानांतर चलती रहे, परंतु इसके कारण सामान्य नागरिकों को मिलने वाली पानी या मकान जैसी प्राथमिक सुविधाएँ किसी भी स्थिति में रुकनी नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि केन्द्र और राज्य सरकार की गरीबोन्मुखी नीतियों के परिणामस्वरूप ही देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। सामान्य नागरिक को अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ आसानी से मिलें; इसके लिए केन्द्र-राज्य सरकार कटिबद्ध है। मकान के लिए जमीन खरीदने में सहायता की आवश्यकता हो, तो सरकार सहायता करने के लिए तत्पर है। ऐसे में पदाधिकारी केवल सक्रिय होकर इन सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाएँ; यह अत्यंत आवश्यक है।

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे को अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया। पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों को निरंतर सीखने और नियमों की मर्यादा में रहकर जनकल्याण के कार्य करने की वृत्ति रखनी चाहिए। चुनाव जीतना या निर्वाचित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया बंद नहीं होती, बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारियाँ और बढ़ती हैं। विधानसभाध्यक्ष ने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, अधिकार और कर्तव्य; दोनों को समझकर पंचायत व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा।

अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी ने आगे कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत - संसद और राज्य की विधानसभा की तरह अब जिला एवं तहसील पंचायत स्तर पर भी सकारात्मक संवाद की संस्कृति विकसित करना आवश्यक है। नागरिकों, कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उचित संवाद ही विकास कार्यों को गति देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में केवल अधिकारों की बात करने के बजाय नागरिकों और जन प्रतिनिधियों; दोनों को अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति भी उतना ही जागृत रहना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की प्रो-एक्टिव कार्यशैली तथा प्रजावत्सल दृष्टिकोण की सराहना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "शासन में 'समस्या का समाधान कैसे लाया जा सकता है'; ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। यह बात हम सभी को मुख्यमंत्री से सीखनी चाहिए।" उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सरकारी नियम और परिपत्र नागरिकों की सुविधा तथा प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए होते हैं, विकास कार्यों को रोकने के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई प्रशासनिक बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे उचित माध्यम से प्रस्तुत करके उसका समाधान लाना चाहिए।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया ने प्रधानमंत्री के 'समृद्ध गाँव' के निर्माण के माध्यम से 'विकसित राष्ट्र' के संकल्प को साकार करने के लिए सभी से सहभागी बनने का आह्वान किया। ग्रामीण विकास को गति देने तथा पंचायतों व स्थानीय निकायों को और अधिक सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि अतीत में ग्राम पंचायतों के पास विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन सीमित थे, जबकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में विकासोन्मुखी योजनाओं की राशि सीधे ही लाभार्थियों और पंचायतों के खातों में जमा हो रही है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री बावळिया ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्य में 45 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है। गोबरधन योजना के माध्यम से 14 हजार से अधिक बायोगैस प्लांट स्थापित करके स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके अलावा; प्रधानमंत्री आवास योजना और वीबी-जीरामजी योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है।

महिला सशक्तीकरण को सरकार की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए उन्होंने मिशन मंगलम और 'लखपति दीदी' जैसी पहलों की सफलता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़ी बहनों को 0 प्रतिशत ब्याज पर ऋण सहायता, उनके उत्पादों की बिक्री के लिए ग्राम हाट की सुविधा तथा सरकारी कार्यालयों और बस स्टैंडों पर कैंटीन संचालन के अवसर उपलब्ध कराकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए 'ड्रोन दीदी' जैसी पहल तथा विभिन्न कौशल-आधारित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को नए अवसरों से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।

विधानसभा के सचिव श्री चेतन पंड्या ने स्वागत संबोधन में कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि 'गणेश वासुदेव मावळंकर संसदीय ब्यूरो' द्वारा आयोजित इस 'पंचायत संस्कार कार्यशाला' का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सक्षम, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनाना है। संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत तथा नैतिक मूल्य अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचें; यही इस आयोजन का अंतिम ध्येय है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान विकेन्द्रीकृत केन्द्रीय नियोजन, 16वें वित्त आयोग और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा। पंचायत-स्थानीय निकाय और नेतृत्व के बीच उत्कृष्ट समन्वय स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्र में शासन एवं कार्यक्षमता के नए मानदंड स्थापित करने का विनम्र प्रयास किया जाएगा।

कार्यशाला के दौरान आयोजित विभिन्न तकनीकी सत्रों में विषय विशेषज्ञों द्वारा पंचायती राज, कानूनी प्रावधानों, जिला योजना, वित्तीय व्यवस्था तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा। गुजरात पंचायत परिषद के आचार्य श्री ए. एच. घासुरा 'पंचायती राज का विकास और पृष्ठभूमि' विषय पर मार्गदर्शन देंगे। सेवानिवृत्त टी.डी.ओ. श्री पी. बी. पटेल 'गुजरात पंचायत अधिनियम के महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों' के संबंध में जानकारी देंगे। सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव श्री जसवंत गांधी द्वारा 'विकेन्द्रीकृत जिला योजना और 16वें वित्त आयोग' के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसके अलावा; सेवानिवृत्त अपर कलेक्टर श्री प्रकाश मोदी राज्य तथा केन्द्र सरकार की पंचायती राज संबंधी योजनाओं के बारे में तथा सेवानिवृत्त सहायक विकास आयुक्त श्री जे. ए. गोहिल ग्रामीण विकास की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में गुजरात पंचायत परिषद के अध्यक्ष श्री वसंतभाई पुरोहित, गुजरात विधानसभा के सचिव श्री चेतन पंड्या, पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री धनंजय द्विवेदी सहित राज्य की सभी जिला और तहसील पंचायतों के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

'पंचायत संस्करण कार्यशाला' समापन समारोह

सत्ता और पद के माध्यम से सेवा के जरिये नागरिकों के दिल में स्थान बनाने का उत्तम अवसर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर : गुजरात विधानसभा में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में पंचायत पदाधिकारियों के लिए आयोजित 'पंचायत संस्करण कार्यशाला' का समापन समारोह आयोजित हुआ। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेश मोदी की विशेष उपस्थिति में आयोजित इस कार्यशाला में त्रिस्तरीय पंचायत के ढाँचे की कार्यप्रणाली और नागरिकों के साथ समन्वय के बारे में विभिन्न सत्र आयोजित हुए।

पंचायत संस्करण कार्यशाला में उपस्थित पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने जमीनी स्तर पर उतरकर अधिक लोकसेवा करने के लिए प्रेरक मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सत्ता और पद केवल कागज पर बने रहने के लिए नहीं हैं, बल्कि सेवा के माध्यम से नागरिकों के दिल में स्थान बनाने का उत्तम अवसर हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात देशभर का ऐसा अग्रणी राज्य है, जहाँ जिला और तहसील पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा स्थायी समिति के अध्यक्ष के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उनके अधिकारों एवं नागरिकों के प्रति उनके दायित्वों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाता है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं को शांतिपूर्वक सुनकर उनका सकारात्मक समाधान लाना आवश्यक है। उन्होंने पदाधिकारियों से दिन के दो घंटे नागरिकों के लिए देने तथा सप्ताह में कम से कम पाँच दिन विभिन्न गाँवों का दौरा कर स्थल पर मौजूद समस्याओं को समझने और अपने स्तर पर उनका निराकरण लाने के लिए कहा।

श्री संघवी ने आगे कहा, "आपको अपने कार्यकाल के दौरान जिला पंचायत के अधीन संपत्तियों पर होने वाले अतिक्रमणों को रोकने, सरकारी स्कूलों की सुविधाओं और शौचालयों की स्थिति सुधारने तथा स्वच्छता अभियान जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।" उन्होंने सभी पदाधिकारियों से जनहित के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा।

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा पंचायत मंत्री श्री ऋषिकेशभाई पटेल का आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया और उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को लोकसेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की शुभकामनाएँ दीं।

समापन समारोह में पंचायत मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत@2047' के संकल्प को सिद्ध करने के लिए गाँवों का सर्वांगीण विकास अनिवार्य है। लोकतंत्र में निर्वाचित जन प्रतिनिधि सीधे जनता से जुड़े होते हैं। नागरिकों की अपेक्षाओं, पीने के पानी, सीवेज, पक्की सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को संवेदनशीलतापूर्वक पूर्ण करना हमारी मुख्य जिम्मेदारी है।

उन्होंने जोड़ा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच से लेकर जिला पंचायत के पदाधिकारियों तक; सभी के लिए पारदर्शिता तथा जवाबदेही के साथ कार्य करना आवश्यक है। विकास कार्यों को गति देने के लिए पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच उचित समन्वय अनिवार्य है। उन्होंने बलपूर्वक आह्वान किया कि अधिकारियों के साथ सकारात्मक विचार-विमर्श करके सरकारी अनुदान एवं योजनाओं का अधिकतम लाभ गाँवों के किसान, खेत मजदूर और अंतिम छोर पर रहने वाले गरीब परिवारों तक पहुँचाएँ।

विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का वास्तविक मूल्यांकन किसी सरकारी सीआर से नहीं, बल्कि जनता के हृदय में अंकित उनके कार्यों से होता है। आधुनिक तकनीक के युग में प्रतिनिधियों को लगातार नया सीखकर अपने कार्यकाल के लिए क्षेत्र के विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार करना चाहिए। लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी एक ही रथ के दो पहियों के समान हैं। इसलिए विकास की गति बनाए रखने के लिए प्रशासनिक नियमों का गहन अध्ययन कर अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करना आवश्यक है। कार्यशाला के अंत में महानुभावों के करकमलों से उपस्थित पदाधिकारियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

इस एक दिवसीय कार्यशाला में विधानसभा के मुख्य सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री संजयसिंह महिडा, गुजरात विधानसभा के सचिव श्री चेतन पंड्या सहित राज्य की सभी जिला और तहसील पंचायतों के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और गति देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री के समक्ष उद्योगकारों तथा जीआईडीसी एसोसिएशन द्वारा की गई प्रस्तुति पर संवेदनशील प्रतिक्रिया - श्री भूपेंद्र पटेल का जीआईडीसी एमनेस्टी योजना लागू करने का निर्णय

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और गति देने वाला महत्वपूर्ण निर्णय किया है।

उद्योगकारों को राहत, सरकारी प्रक्रिया में सरलता और औद्योगिक विकास को वेग देने के दृष्टिकोण के साथ राज्य सरकार उद्योग क्षेत्र के लिए सरल, पारदर्शी और विकासोन्मुखी प्रशासन के लिए निरंतर कार्यरत है।

जीआईडीसी के प्लॉट धारकों द्वारा औद्योगिक प्लॉट अथवा शेड के हस्तांतरण के समय पक्षकारों को रजिस्टर्ड लीज डीड करके देने के बजाय केवल अलॉटमेंट लेटर या सप्लिमेंटरी एग्रीमेंट दिया जाता है। इसके कारण पूर्व के प्लॉट धारकों द्वारा अधिकांशतः स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है।

राज्य सरकार ने दिनांक 02/04/25 से गुजरात स्टांप अधिनियम, 1958 में समन्वित संशोधन किए हैं। इसके अंतर्गत गुजरात स्टांप अधिनियम की धारा-39 (1)(ख) में किए गए संशोधन के अनुसार पक्षकार विलेख (कानूनी दस्तावेज) पर उचित ड्यूटी/बकाया स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए मूल विलेख स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है, तो विलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रत्येक माह के लिए बकाया स्टांप ड्यूटी की 2 प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि, विलेख पर बकाया स्टांप ड्यूटी की चार गुना से अधिक न हो; इतनी दंड की राशि तथा यदि सरकारी प्रशासन द्वारा जाँच कर विलेख जब्त किया गया हो, तो विलेख पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रत्येक माह के लिए बकाया स्टांप ड्यूटी की 3 प्रतिशत साधारण ब्याज की राशि, विलेख पर बकाया स्टांप ड्यूटी की छह गुना से अधिक न हो; इतनी दंड राशि वसूल करने का प्रावधान दिनांक 10/04/25 से राज्य में लागू हुआ है।

इसके परिणामस्वरूप जब वर्तमान मालिक को ऋण या अन्य आवश्यकता के लिए लीज डीड करनी हो, तब पिछले सभी लेन-देन की बकाया ड्यूटी असहनीय दंड के साथ भरने का बोझ उन पर आता है।

इस संदर्भ में राज्य के उद्योगकारों तथा जीआईडीसी एसोसिएशनों की ओर से प्राप्त प्रस्तुतियों पर संवेदनापूर्वक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जीआईडीसी के औद्योगिक प्लॉट के पूर्व के हस्तांतरण लेन-देन में बकाया रह गई स्टांप ड्यूटी एवं उस पर लगने वाली पैनल्टी के बोझ से पात्र एमएसएमई उद्योगों को राहत देने के लिए जीआईडीसी एमनेस्टी स्कीम लागू करने का निर्णय लिया है।

इस योजना के परिणामस्वरूप पुराने लेन-देन के कारण हाल के प्लॉट धारकों पर आन पड़े भारी स्टांप ड्यूटी तथा पैनल्टी के बोझ में कमी आएगी।

जीआईडीसी एमनेस्टी स्कीम क्या है ?

जीआईडीसी के प्लॉट धारकों द्वारा अतीत में औद्योगिक प्लॉट या शेड के आवंटन के समय कई मामलों में रजिस्टर्ड दस्तावेज के बजाय अलॉटमेंट लेटर, सप्लिमेंटरी एग्रीमेंट आदि दस्तावेज किए गए थे। परिणामस्वरूप पूर्व के चरण के कुछ लेन-देन में उचित स्टांप ड्यूटी का भुगतान नहीं हो सका था। ऐसे पुराने लेन-देन में वर्तमान मालिक के समक्ष लीज डीड या अन्य आवश्यक दस्तावेज का पंजीकरण करवाते समय पूर्व के लेन-देन की बकाया स्टांप ड्यूटी तथा भारी दंड भरने की समस्या उत्पन्न होती थी।

इस संदर्भ में उद्योगकारों तथा जीआईडीसी एसोसिएशनों की ओर से राज्य सरकार को प्राप्त प्रस्तुतियों को ध्यान में लेकर इस समस्या के व्यावहारिक समाधान के लिए एमनेस्टी योजना शुरू की जाएगी।

एमएसएमई उद्योगकारों को स्टांप ड्यूटी में मिलेगी 80 प्रतिशत तक की राहत

इस योजना के अनुसार पात्र मामलों में लागू स्टांप ड्यूटी में से 80 प्रतिशत तक की राशि माफ करके केवल 20 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी तथा लागू पैनल्टी वसूल करने का प्रस्ताव है, लेकिन जहाँ 20 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी और पैनल्टी की कुल राशि मूल स्टांप ड्यूटी से कम होती हो, ऐसे मामलों में मूल स्टांप ड्यूटी जितनी राशि वसूल की जाए; इस प्रकार राहत का लाभ दिया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप अतीत के लेन-देन के कारण वर्तमान प्लॉट धारकों पर पड़ने वाले बड़े वित्तीय बोझ में उल्लेखनीय कमी आएगी।

किसे मिलेगा लाभ ?

एमनेस्टी स्कीम का लाभ मुख्यतः एमएसएमई प्रकार के उद्योगों अर्थात मान्य उद्यम सर्टिफिकेट रखने वाली इकाइयों को देने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 30 जून, 2025 तक हुए पात्र अलॉटमेंट लेटर, शेयर ट्रांसफर, किराया पट्टा/उप-किराया पट्टा तथा संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित अन्य पात्र लेन-देन को शामिल किया जाएगा।

पंजीकरण अनिवार्य रहेगा

ऐसी राहत का लाभ प्राप्त करने वाले वर्तमान आवंटी को लागू स्टांप ड्यूटी तथा पैनल्टी की राशि का भुगतान करना होगा और संबंधित संपत्ति का कानूनी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

इससे एक ओर उद्योगकारों को वित्तीय राहत मिलेगी और दूसरी ओर संपत्ति के लेन-देन को कानूनी तथा पारदर्शी पंजीकरण व्यवस्था में लाने में मदद मिलेगी।

अपील और कोर्ट मामलों में भी समाधान का अवसर

जीआईडीसी से संबंधित स्टांप ड्यूटी के मामलों में जहाँ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील की गई हो और नियम के अनुसार 25 प्रतिशत राशि जमा कराई गई हो, ऐसे पात्र मामलों में निर्धारित शर्तों के अधीन इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

इसी प्रकार कोर्ट में पिटिशन दाखिल की गई हो, ऐसे मामलों में पिटिशन वापस लेने की शर्त पर पात्रता के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने का प्रावधान प्रस्तावित है।

1 जनवरी, 2018 से पहले के लेन-देन के लिए भी विशेष राहत

दिनांक 01/01/2018 से पहले हुए हस्तांतरण के मामलों में पूर्व के हस्तांतरणों में से अंतिम हस्तांतरण के विलेख पर निर्धारित बाजार मूल्य के आधार पर लागू होने वाली स्टांप ड्यूटी में 80 प्रतिशत राहत देकर शेष 20 प्रतिशत ड्यूटी तथा लागू पैनल्टी वसूल करने का प्रस्ताव है।

इतना ही नहीं, दिनांक 01/01/2018 अथवा उसके बाद हुए हस्तांतरणों की स्टांप ड्यूटी वसूल किए जाने योग्य हो, ऐसे सभी मामलों में लागू स्टांप ड्यूटी में से 80 प्रतिशत राहत देकर 20 प्रतिशत ड्यूटी तथा लागू पैनल्टी वसूल करने का प्रस्ताव इस योजना में है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार द्वारा की गई इस पहल से पुराने बकाया लेन-देन के कारण उत्पन्न हुई कठिनाइयों का व्यावहारिक समाधान लाने में सहायता मिलेगी। उद्योगकारों को वित्तीय राहत मिलने के साथ लंबे समय से बकाया स्टांप ड्यूटी की वसूली भी तेज हो सकेगी।

साथ ही संपत्ति के लेन-देन का कानूनी पंजीकरण होने से लेन-देन में पारदर्शिता और नियमितता बढ़ेगी तथा राज्य में नए उद्योग स्थापित करने और वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

त्योहारों में मिठास पर सरकार की नजर, चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए डीलरों की स्टॉक सीमा आधी

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देशभर में चीनी डीलरों के लिए निर्धारित स्टॉक सीमा को आधा कर दिया है। अब 15 सितंबर से देश के अधिकांश हिस्सों में चीनी डीलर अधिकतम 2,000 क्विंटल चीनी का ही स्टॉक रख सकेंगे। यह व्यवस्था 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। सरकार का मानना है कि त्योहारी मांग बढ़ने के दौरान जमाखोरी और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाकर बाजार में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी और उपभोक्ताओं को अनावश्यक मूल्य वृद्धि से राहत मिलेगी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी व्यवस्था के अनुसार, यह निर्णय बाजार की स्थिति और आगामी त्योहारों के दौरान चीनी की संभावित बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। त्योहारों के समय मिठाइयों, बेकरी उत्पादों और अन्य खाद्य पदार्थों में चीनी की खपत बढ़ जाती है। मांग में अचानक वृद्धि के दौरान यदि बाजार में बड़े पैमाने पर स्टॉक जमा किया जाता है तो कीमतों में कृत्रिम तेजी आने की आशंका रहती है। सरकार इसी संभावना को देखते हुए डीलरों के पास रखे जाने वाले स्टॉक पर नियंत्रण मजबूत कर रही है।

सरकार ने इससे पहले 1 अगस्त से देशभर के चीनी डीलरों के लिए 4,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा तय की थी। उस समय डीलरों को एक निश्चित मात्रा तक चीनी रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में बाजार में जमाखोरी और सट्टेबाजी से जुड़ी शिकायतें सामने आने के बाद सरकार ने स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद स्टॉक सीमा को घटाकर 2,000 क्विंटल करने का फैसला किया गया है।

यानी पहले की तुलना में डीलरों को अब आधी मात्रा में ही चीनी रखने की अनुमति होगी। सरकार की नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चीनी की बड़ी मात्रा कुछ व्यापारियों या डीलरों के पास लंबे समय तक जमा न रहे। यदि बाजार में मांग बढ़ती है और पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध होने के बावजूद बड़े कारोबारी उसे रोककर रखते हैं तो कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। ऐसी स्थिति में खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। स्टॉक सीमा कम करके सरकार इसी तरह की संभावित स्थिति को रोकना चाहती है। नए नियमों के तहत डीलरों को चीनी प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक उसका स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही किसी भी स्थान पर एक समय में 2,000 क्विंटल से अधिक चीनी रखने पर रोक रहेगी। इससे कारोबारियों को अपने स्टॉक का नियमित रूप से प्रबंधन करना होगा और पुराना माल बाजार में भेजना होगा। सरकार की कोशिश है कि चीनी की आपूर्ति लगातार बनी रहे और बाजार में किसी एक समय पर बड़ी मात्रा में स्टॉक रोककर रखने की स्थिति पैदा न हो। स्टॉक सीमा का यह प्रावधान विशेष रूप से त्योहारी अवधि में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सितंबर से नवंबर तक देश के कई हिस्सों में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं और इस दौरान मिठाई तथा अन्य खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ती है। चीनी इन उत्पादों के प्रमुख कच्चे माल में शामिल है।

125 करोड़ की लागत से भावनगर परा यार्ड रीमॉडलिंग कार्य को मिली मंजूरी,रेल परिचालन क्षमता में होगा उल्लेखनीय विस्तार, यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

यात्रियों को बेहतर, सुगम एवं सुविधाजनक रेल यात्रा उपलब्ध कराने तथा भावनगर क्षेत्र में रेल परिचालन क्षमता को और सुदृढ़ करने की दिशा में पश्चिम रेलवे द्वारा महत्वपूर्ण पहल की गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा भावनगर परा यार्ड के व्यापक रीमॉडलिंग एवं उन्नयन कार्य के लिए लगभग 125 करोड़ की लागत वाली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने के बाद भावनगर क्षेत्र में रेल परिचालन को नई गति मिलेगी। भावनगर टर्मिनस पर परिचालन संबंधी दबाव कम होगा तथा भविष्य में अधिक संख्या में ट्रेनों के संचालन की क्षमता विकसित होगी। इससे ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

भावनगर परा यार्ड में विकसित होंगी आधुनिक सुविधाएं

परियोजना के अंतर्गत भावनगर परा यार्ड में यात्री सुविधाओं एवं रेल परिचालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से:

एक नए प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा तथा मौजूदा प्लेटफॉर्म को चौड़ा किया जाएगा, जिससे यात्रियों के आवागमन में और सुविधा होगी। यात्रियों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए नए फुट ओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण किया जाएगा तथा मौजूदा फुट ओवर ब्रिज का विस्तार किया जाएगा। स्टेशन परिसर एवं यात्री क्षेत्रों में बेहतर एवं उन्नत यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

रेल परिचालन क्षमता में होगा उल्लेखनीय विस्तार

भावनगर परा यार्ड रीमॉडलिंग के तहत रेल परिचालन को अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए 4 नई लूप लाइनों का निर्माण किया जाएगा, 1 नई इंजन रिवर्सल लाइन विकसित की जाएगी। ट्रेनों की स्टेब्लिंग एवं मेंटेनेंस संबंधी सुविधाओं को भावनगर परा में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे भावनगर टर्मिनस पर परिचालन क्षमता का बेहतर उपयोग संभव होगा और वहां अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होगी। सड़क यातायात को सुचारु बनाने के लिए नए रेल अंडरपास (RUB) का निर्माण किया जाएगा।

भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग होगा प्रशस्त

भावनगर परा यार्ड के इस व्यापक उन्नयन से रेल परिचालन की क्षमता एवं दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यार्ड में अतिरिक्त लाइनें, स्टेब्लिंग एवं मेंटेनेंस सुविधाएं विकसित होने से ट्रेनों के संचालन को अधिक सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस परियोजना से भावनगर टर्मिनस पर परिचालन दबाव कम होगा, ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार होगा और भविष्य में भावनगर से अधिक ट्रेनों के संचालन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार होगी। साथ ही, यात्रियों को बेहतर प्लेटफॉर्म, फुट ओवर ब्रिज एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

यह महत्वपूर्ण परियोजना भावनगर क्षेत्र के रेल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा यात्री सुविधाओं एवं रेल परिचालन को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विचार मंत्र को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल आत्मसात कर रहें हैं

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'नागरिक भागीदारी द्वारा सुशासन' के विचार मंत्र को साकार करने की दिशा में गुजरात सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके अंतर्गत भारत सरकार के साथ-साथ गुजरात सरकार द्वारा भी राज्य में 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जयंती तक 'रिफॉर्म उत्सव' मनाया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों से प्राप्त प्रस्तुतियों और सुझावों में से पद्धतिगत सुधार के सुझावों की पहचान करना, उनका वर्गीकरण करना और समयबद्ध तरीके से उन्हें लागू करना है, जो संपूर्ण व्यवस्था में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल प्रशासनिक सुधार को लेकर बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं और उन्होंने गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन भी किया है। इसी दिशा में भारत सरकार की पहल से मनाए जाने वाला यह 'रिफॉर्म उत्सव' केवल शिकायत निवारण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नागरिक के सुझाव को एक कार्यक्षम सुधार में परिवर्तित कर उसे लागू करने का व्यवस्थित प्रयास बनेगा। अभियान का अंतिम उद्देश्य यह है कि नागरिक की आवाज सुझाव से आगे बढ़कर लागू किए जा सकने वाले सुधार में परिवर्तित हो और उसके परिणाम लोगों तक पहुँचें।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री के सीधे नेतृत्व में कार्यरत सामान्य प्रशासन विभाग ने रिफॉर्म उत्सव के प्रभावी आयोजन, संचालन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में सदस्यों के रूप में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव रहेंगे। आवश्यकता के अनुसार अन्य अधिकारियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, रिफॉर्म उत्सव के समन्वय के लिए राज्य

स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव (प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण प्रभाग) को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक प्रशासनिक विभाग और जिले में भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, ताकि अभियान के प्रत्येक चरण का कामकाज व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े।

जिला स्तर पर भी मजबूत क्रियान्वयन व्यवस्था

रिफॉर्म उत्सव को केवल गांधीनगर या राज्य स्तर की पहल न रखते हुए इसे सुदूरवर्ती नागरिक तक पहुँचाने के लिए जिला स्तर पर भी समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में कलेक्टर और सह-अध्यक्ष के रूप में जिला विकास अधिकारी रहेंगे। निवासी अपर कलेक्टर सहित कृषि, स्वास्थ्य, समाज सुरक्षा, बैंकिंग, बिजली कंपनी और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी इसमें स्थान दिया गया है।

इस व्यवस्था से स्थानीय स्तर पर मिलने वाले सुझावों का संकलन, संबंधित विभागों के साथ समन्वय और नागरिकों की भागीदारी को अधिक गति मिलेगी। रिफॉर्म उत्सव पोर्टल पर प्राप्त सुझावों और उनके क्रियान्वयन की प्रगति को भी लगातार ट्रैक करने की व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर सुझावों की संख्या, क्रियान्वयन के लिए स्वीकार किए गए सुधार और उनकी लाइव स्थिति उपलब्ध रहेगी।

2 अक्टूबर से 'जन मंथन' : प्रत्येक पंचायत में नागरिकों की सीधी भागीदारी

गांधी जयंती अर्थात 2 अक्टूबर से रिफॉर्म उत्सव का मुख्य चरण शुरू होगा। इसमें प्रत्येक पंचायत में 'जन मंथन सभा' आयोजित की जाएगी। इस सभा में वरिष्ठ महानुभावों के संबोधन के साथ नागरिकों को रिफॉर्म उत्सव के बारे में जागरूक किया जाएगा। नागरिकों को मौके पर ही अपने सुझाव प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए माय भारत वॉलंटियर्स और कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हेल्प डेस्क भी कार्यरत किए जाएँगे।

अक्टूबर के दौरान वार्ड सभा, जनसभा, रैली, वॉकथॉन, साइकिल और बाइक रैली, नुक्कड़ नाटक, कैंपस आउटरीच, महिला स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, व्यापारी मंडलों, सहकारी संस्थाओं, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों और हाउसिंग सोसायटियों सहित विभिन्न स्तरों पर जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएँगी। आशा, एएनएम और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर संपर्क करके भी लोगों तक अभियान का संदेश पहुँचाया जाएगा।

'विचार' से 'प्रशासनिक व्यवस्था' तक : तीन चरणों में सुधार की प्रक्रिया

रिफॉर्म उत्सव में पहला चरण 'जन मंथन' का होगा, जिसमें 2 से 31 अक्टूबर तक नागरिकों के सुझाव एकत्र किए जाएँगे। इसके बाद 10 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 'विमर्श' चरण में विभाग सुझावों का गहन विश्लेषण करके लागू किए जा सकने वाले सुधारों की पहचान करेंगे और उन्हें 'क्विक विंस' तथा 'मध्यम अवधि के सुधार' के रूप में वर्गीकृत करेंगे।

तीसरे चरण 'जन समाधान' में 10 अक्टूबर से 20 दिसंबर तक क्विक विंस का क्रियान्वयन किया जाएगा। मध्यम अवधि के सुधारों के लिए क्रियान्वयन का रोडमैप तैयार करके पोर्टल पर रखा जाएगा और उसके क्रियान्वयन की शुरुआत भी की जाएगी।

शिकायत नहीं, व्यवस्था में सुधार का सुझाव बनेगा रिफॉर्म

रिफॉर्म उत्सव की विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रस्तुति को स्वचालित रूप से 'रिफॉर्म' नहीं माना जाएगा। कोई सुझाव सामान्य परिस्थिति में सभी पर लागू हो, मूल समस्या के कारण को संबोधित-केंद्रित करे, भविष्य की प्रक्रिया में सुधार लाए, मानक नियम या मानक संचालन पद्धति के रूप में अन्य स्थानों पर भी लागू किया जा सके और रचनात्मक समाधान सुझाए; इन पाँच कसौटियों के आधार पर उसे रिफॉर्म के रूप में पहचाना जाएगा। इस प्रकार; गुजरात में 'रिफॉर्म उत्सव' नागरिक और सरकार के बीच संवाद को नई दिशा देने वाला अभियान बनेगा। लोगों के अनुभवों और सुझावों को प्रशासनिक सुधार के साधन में परिवर्तित करके अधिक सरल, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित सुशासन की दिशा में गुजरात एक और मजबूत कदम उठाएगा। दिसंबर के अंत में 'संकल्प सिद्धि' के माध्यम से सफल सुधारों और उत्कृष्ट कार्यों को उजागर करके भविष्य के लिए संकल्पों को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।

अनाज वितरण व्यवस्था में डिजिटल क्रांति

राज्य में टेक्नोलॉजी से अधिक सुदृढ़ बन रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली : जीपीएस टेक्नोलॉजी और लगभग 7 हजार सीसीटीवी कैमरों द्वारा अनाज वितरण की सटीक-सतत मॉनिटरिंग

राज्यभर के 250 गोदामों द्वारा लगभग 17 हजार उचित मूल्य की दुकानों तक अनाज का वितरण

गांधीनगर : गुजरात सरकार के संयुक्त उपक्रम 'गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि.' (जीएससीएससीएल) द्वारा राज्य के 250 गोदामों से लगभग 17 हजार पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार-उचित मूल्य की दुकानों-एफपीएस तक अनाज और अन्य वस्तुओं के वितरण में तेजी और पूर्ण पारदर्शिता लाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी अपनाई गई है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी के मार्गदर्शन में सप्लाई चेन ऑपरेशन को डिजिटल बनाने के लिए निगम द्वारा आईसीटी लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा एफसीआई के डिपो से लेकर राज्य के गोदामों और एफपीएस तक वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग होती है। वाहनों में जीपीएस सिस्टम और मशीन लर्निंग आधारित 'रूट ऑप्टिमाइजेशन' लागू किया गया है। निर्धारित रूट से वाहन डायवर्ट हो या जीपीएस डिस्कनेक्ट हो जाए, तो तुरंत सिस्टम में अलर्ट जनरेट होता है।

गोदाम और एफपीएस में जियो-फेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ ऑफ डिलीवरी (ईपीओडी) से मात्रा प्राप्त होने की सटीक पुष्टि की जाती है।

इसके अलावा; मुख्य कार्यालय में स्थापित 'कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर' से सभी संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। इसके अलावा; पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-पीडीएस पोर्टल के माध्यम से गोदाम में स्टॉक की लाइव जानकारी और दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक डैशबोर्ड रिपोर्ट उपलब्ध होती हैं। इसे आईसीटी लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट और एफसीआई के 'अन्न दर्पण' पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अलावा; गोदाम में चोरी, मिलावट रोकने और सुरक्षा के लिए लगभग 7 हजार सीसीटीवी कैमरे, जिनमें बुलेट, डोम, पीटीजेड और एएनपीआर जैसे कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग के लिए गोदाम, उप जिला प्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी के कार्यालयों और मुख्य कार्यालय में कमांड-कंट्रोल सेंटर के साथ 'वीडियो वॉल' का अत्याधुनिक सेटअप व्यवस्थित किया गया है।

फार्मर प्रोक्योरमेंट पोर्टल

इसके अलावा; किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की खरीद के लिए फार्मर प्रोक्योरमेंट पोर्टल (एफपीपी) कार्यरत है। जिसमें आधार कार्ड, बैंक विवरण और भूमि के आधार-प्रमाण की डेमोग्राफिक तथा बायोमेट्रिक जाँच के बाद ही रजिस्ट्रेशन और खरीद होती है तथा प्रत्येक चरण पर एसएमएस के माध्यम से किसानों को जानकारी भी दी जाती है।

मानसून में त्वचा को दें 'ब्यूटी ब्रेक', शहनाज हुसैन बता रही हैं स्किन फास्टिंग का सही तरीका

मानसून का मौसम गर्मी से राहत जरूर देता है, लेकिन त्वचा के लिए यह मौसम कई तरह की चुनौतियां लेकर आता है। वातावरण में नमी बढ़ने के कारण त्वचा पर चिपचिपाहट, अतिरिक्त तेल, पसीना, धूल और प्रदूषण का असर अधिक दिखाई देने लगता है। इसके साथ ही लगातार बारिश और उमस के कारण त्वचा की प्राकृतिक संतुलन प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस मौसम में कई लोगों को कील-मुंहासे, रैशेज, लालिमा, फोड़े-फुंसी और त्वचा में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में त्वचा की देखभाल के लिए एक नया विचार चर्चा में है, जिसे 'स्किन फास्टिंग' कहा जाता है। स्किन फास्टिंग का सामान्य अर्थ कुछ समय के लिए त्वचा पर इस्तेमाल किए जाने वाले सौंदर्य प्रसाधनों और स्किन केयर उत्पादों को कम करना या रोकना है। क्रीम, सीरम, टोनर, फेशियल ऑयल और मेकअप जैसी कई चीजों का हम अपनी त्वचा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नियमित इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी-कभी जरूरत से ज्यादा उत्पादों का इस्तेमाल त्वचा पर अतिरिक्त भार डाल सकता है। ऐसे में स्किन फास्टिंग के माध्यम से त्वचा को कुछ समय के लिए आराम देने की अवधारणा सामने आती है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौंदर्य विशेषज्ञ और 'हर्बल क्वीन' के रूप में लोकप्रिय शहनाज हुसैन के अनुसार मानसून में स्किन फास्टिंग को त्वचा के लिए एक तरह के 'ब्यूटी ब्रेक' के रूप में समझा जा सकता है। जिस तरह लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार व्रत रखकर शरीर और मन को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह स्किन फास्टिंग में त्वचा को अनावश्यक सौंदर्य प्रसाधनों से कुछ समय के लिए राहत देने की कोशिश की जाती है। इसका उद्देश्य त्वचा को उसके प्राकृतिक तरीके से काम करने का अवसर देना है।

आज के समय में त्वचा की देखभाल के नाम पर बाजार में अनेक प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं। मॉइस्चराइजर से लेकर सीरम, टोनर, एक्सफोलिएटर, फेस ऑयल और विभिन्न प्रकार के मास्क तक लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। कई लोग एक साथ कई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे त्वचा जल्दी चमकदार और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन हर उत्पाद हर व्यक्ति की त्वचा के लिए उपयुक्त हो, यह जरूरी नहीं है। लगातार नए उत्पादों का प्रयोग करने से कभी-कभी यह समझना भी मुश्किल हो जाता है कि त्वचा को वास्तव में किस चीज की आवश्यकता है।

स्किन फास्टिंग इसी बात को समझने का एक अवसर दे सकती है। जब त्वचा को कुछ समय के लिए अनावश्यक कॉस्मेटिक उत्पादों से दूर रखा जाता है तो व्यक्ति अपनी त्वचा की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बेहतर तरीके से समझ सकता है। इस दौरान यह महसूस किया जा सकता है कि त्वचा सामान्य स्थिति में कैसी रहती है और किन उत्पादों के इस्तेमाल के बाद उसमें सुधार या परेशानी दिखाई देती है। इससे भविष्य में अपनी स्किन केयर रूटीन को अधिक सरल और जरूरत के अनुसार बनाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि स्किन फास्टिंग का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि त्वचा की बुनियादी सफाई और सुरक्षा भी बंद कर दी जाए। त्वचा की स्वच्छता हमेशा जरूरी है। चेहरे को साफ रखना, आवश्यकता के अनुसार मॉइस्चराइज करना और धूप से त्वचा की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। खासतौर पर सनस्क्रीन को पूरी तरह बंद करना उचित नहीं माना जाना चाहिए। मानसून में बादल होने के बावजूद सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव त्वचा पर पड़ सकता है। इसलिए दिन में बाहर निकलते समय उपयुक्त सनस्क्रीन का इस्तेमाल त्वचा की सुरक्षा के लिए जरूरी हो सकता है।

स्किन फास्टिंग शुरू करने वालों के लिए इसे अचानक और पूरी तरह अपनाने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ना बेहतर माना जाता है। शुरुआत रात से की जा सकती है। रात में चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद यदि त्वचा को किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं है तो कुछ समय के लिए अनावश्यक कॉस्मेटिक उत्पादों को न लगाने का प्रयास किया जा सकता है। सुबह चेहरे को सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से साफ किया जा सकता है। यदि त्वचा इस बदलाव को आसानी से स्वीकार कर ले तो व्यक्ति अपनी जरूरत और त्वचा की प्रकृति के अनुसार इसे आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है। किसी की त्वचा तैलीय होती है, किसी की शुष्क, जबकि कुछ लोगों की त्वचा संवेदनशील हो सकती है। इसलिए जो तरीका एक व्यक्ति के लिए ठीक हो, जरूरी नहीं कि वह दूसरे के लिए भी उतना ही उपयुक्त हो। शुष्क त्वचा वाले लोगों को मॉइस्चराइजिंग की जरूरत बनी रह सकती है। यदि त्वचा बहुत अधिक रूखी, खिंची हुई या असहज महसूस हो तो केवल ट्रेंड के नाम पर मॉइस्चराइजर पूरी तरह बंद करना उचित नहीं होगा। इसी तरह संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को पहले से त्वचा संबंधी परेशानी है तो बिना विशेषज्ञ की सलाह के स्किन फास्टिंग करना सही कदम नहीं हो सकता। कील-मुंहासे, चकत्ते, लगातार लालिमा, जलन या अन्य त्वचा समस्याओं से परेशान लोगों को अपनी त्वचा की जरूरतों के अनुसार उपचार और देखभाल करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आवश्यक त्वचा देखभाल उत्पादों को केवल स्किन फास्टिंग के नाम पर बंद कर देना परेशानी बढ़ा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की एक और विद्यार्थी हितैषी पहल

गुजरात सरकार का बड़ा निर्णय : अब निजी स्कूल-कॉलेजों के एनसीसी कैडेट्स को भी मिलेंगे कैम्प भत्ते

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने नेशनल कैडेट कॉर्प्स (एनसीसी) के कैडेट्स के हित में महत्वपूर्ण तथा समान अवसर आधारित निर्णय किया है। इस निर्णय के अनुसार अब राज्य के निजी स्कूल-कॉलेजों में कार्यरत एनसीसी कैडेट्स जब राष्ट्रीय स्तर के कैम्प के लिए चयनित होंगे, तब उन्हें सरकारी स्कूल-कॉलेज के कैडेट्स की तरह ही कैम्प भत्ते मिलेंगे।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युम्न वाजा तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय से निजी संस्थान के कैडेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर समान अवसर प्राप्त करने में आने वाली आर्थिक बाधा दूर होगी।

उल्लेखनीय है कि एनसीसी कैडेट्स के लिए Republic Day Contingent (RDC), Thal Sainik Camp (TSC), Youth Exchange Programme (YEP), Vayu Sainik Camp (VSC), Naval Sainik Camp (NSC) और National Level Event (NLE) जैसे राष्ट्रीय स्तर के कैम्प महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कैम्पों में चयनित होने के लिए कैडेट्स को प्रतिस्पर्धात्मक चयन प्रक्रिया

से गुजरना पड़ता है और लगभग 4 से 5 प्रतिस्पर्धात्मक कैम्पों में भाग लेना पड़ता है।

अब तक राज्य के सरकारी स्कूल-कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार विभिन्न कैम्प भत्ते दिए जाते थे, जबकि निजी स्कूल-कॉलेजों के कैडेट्स को राज्य या केन्द्र सरकार की ओर से ऐसे कोई भत्ते नहीं मिलते थे। परिणामस्वरूप कैम्प से जुड़ा खर्च कैडेट या संस्थान को स्वयं वहन करना पड़ता था। आर्थिक बोझ के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने की क्षमता रखने वाले कुछ प्रतिभाशाली कैडेट्स भी भाग लेने में हिचकिचाते होने की स्थिति सरकार के ध्यान में आई थी।

इस स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा विभाग ने एक प्रस्ताव कर अब निजी स्कूल-कॉलेजों के कैडेट्स को भी सरकारी कैडेट्स के समान कैम्प भत्ते देने का निर्णय किया है। विशेष बात यह है कि इसके लिए होने वाले खर्च का 100 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। भत्ते का भुगतान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दर के अनुसार किया जाएगा।

इस निर्णय से मेसिंग, ट्रैवलिंग, जनरेशन, इंसिडेंटल और POL चार्जेस जैसे कैम्प संबंधित खर्चों में कैडेट्स और उनके संस्थानों को सीधी राहत मिलेगी। सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्रतिभाशाली कैडेट को समान अवसर उपलब्ध कराना है। कैडेट सरकारी संस्थान में अध्ययन करता है या निजी संस्था में; उसका राष्ट्रीय स्तर का अवसर अब आर्थिक क्षमता पर आधारित नहीं रहेगा। चयन प्रतिभा, मेहनत और क्षमता के आधार पर होगा।

एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व, दायित्व और राष्ट्रसेवा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के कैम्पों में गुजरात के अधिक से अधिक कैडेट्स भाग लें और अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करें; यह राज्य के युवा विकास के लिए भी सकारात्मक परिणाम देने वाला कदम बन सकता है।

राज्य सरकार ने इस निर्णय से निजी तथा सरकारी संस्थानों के एनसीसी कैडेट्स के बीच आर्थिक सुविधा की असमानता दूर की है। अब प्रतिभाशाली कैडेट्स के लिए आर्थिक बाधा नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा ही राष्ट्रीय मंच तक पहुँचने का मुख्य आधार बनेगी।

गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को लाभांश राशि 15.37 करोड़ रुपए के चेक सौंपें

राज्य में 1156 एग्री बिजनेस सेंटर्स के जरिए निगम फर्टिलाइजर, नॉन फर्टिलाइजर और एग्रो इनपुट्स की बिक्री करता है

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को मंगलवार को गांधीनगर में राज्य सरकार के उपक्रम गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लाभांश के रूप में क्रमशः 11.14 करोड़ रुपए तथा 4.23 करोड़ रुपए सहित कुल 15.37 करोड़ रुपए के चेक सौंपे। यह निगम राज्य में 1969 से कार्यरत है और इसका मुख्य उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक का सीधा वितरण, कृषि मशीनरी-टूल्स का उत्पादन और वितरण तथा एग्रो प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग उद्योगों की स्थापना एवं कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। कृषि राज्य मंत्री श्री रमेशभाई कटारा और कृषि, किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा ने मुख्यमंत्री को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के यह लाभांश चेक सौंपें।

मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि राज्य सरकार का यह उपक्रम लगभग 1156 एग्री बिजनेस सेंटर्स के जरिए किसानों को फर्टिलाइजर और नॉन फर्टिलाइजर एग्रो इनपुट की बिक्री करता है।

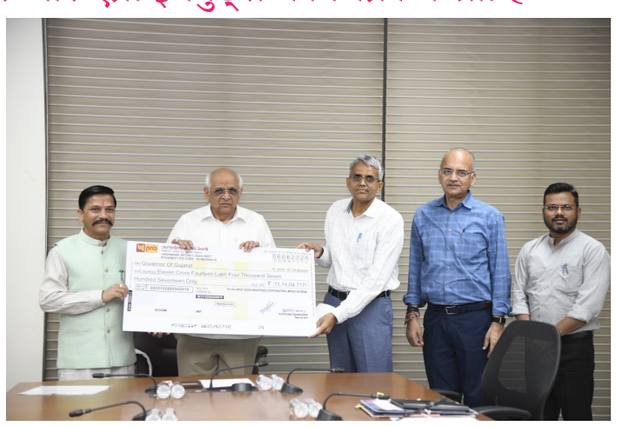

इतना ही नहीं, बावळा, अहमदाबाद एयरपोर्ट, झगड़िया, नरोड़ा और महुवा में विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। निगम ने अहमदाबाद के त्रागड़ में एग्री बिजनेस एंड इनोवेशन हब के निर्माण का कार्य शुरू किया है।

प्रधान सचिव श्री आर.सी. मीणा ने मुख्यमंत्री को गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज की जीआई टैग, मिलेट वैल्यू एडिशन यूनिट, बनाना फाइबर एक्सट्रैक्शन और पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने संबंधी दूसरी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को यह लाभांश चैक सौंपने के अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक श्री विजय खराड़ी भी मौजूद रहे।

भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग के 5 कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए डीआरएम अवार्ड से किया गया सम्मानित,गुड्स डिलिंग, वैगन टर्न अराउंड में सुधार एवं ग्राहक समन्वय में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला सम्मान

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के वाणिज्य विभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले 5 कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डीआरएम अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समारोह 31 अगस्त 2026 को भावनगर मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सम्मानित कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए तथा उनके उत्कृष्ट कार्य की सराहना की। उन्होंने कर्मचारियों को निरंतर इसी समर्पण, कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए रेल सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वाणिज्य विभाग के इन कर्मचारियों ने गुड्स डिलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए वैगन टर्न अराउंड में सुधार, ग्राहकों के साथ प्रभावी समन्वय तथा परिचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी समाधान में उल्लेखनीय

योगदान दिया है। उनकी कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण एवं विषय की गहरी समझ से माल यातायात से संबंधित कार्यों में दक्षता एवं गुणवत्ता को बढ़ावा मिला है।

डीआरएम अवार्ड से सम्मानित कर्मचारी वाणिज्य विभाग में गुड्स डिलिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को डीआरएम अवार्ड से सम्मानित किया गयाः

1. श्री कल्लू राम सैनी – मुख्य वाणिज्य लिपिक, पीपावाव
2. श्री पंकज खोरसिया – कोचिंग सुपरवाइजर, आद्रि
3. श्री कौशिक मकवाना – मुख्य वाणिज्य लिपिक, जूनागढ़
4. श्री यतिन राठोड – कोचिंग सुपरवाइजर, वरतेज
5. श्री राहुल यादव – मुख्य वाणिज्य लिपिक, पीपावाव

इन कर्मचारियों द्वारा माल यातायात से संबंधित कार्यों में बेहतर समन्वय एवं कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने के साथ-साथ Wagon Turn Around में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त, ग्राहकों के साथ समुचित समन्वय स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं एवं आकस्मिक रूप से उत्पन्न समस्याओं का त्वरित समाधान करने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने वाणिज्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसी प्रकार समर्पण, कार्यकुशलता और उत्कृष्टता के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रेल परिचालन की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ ग्राहकों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भावनगर मंडल में 'राजभाषा माह-2026' का भव्य शुभारंभ,मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई राजभाषा शपथ

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में 'राजभाषा माह-2026' का शुभारंभ 01 सितंबर 2026 को गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में राजभाषा शपथ समारोह के साथ हुआ। मंडल कार्यालय परिसर में आयोजित समारोह में मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग एवं प्रसार की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा, सभी शाखा अधिकारी, वरिष्ठ पर्यवेक्षक तथा बड़ी संख्या में रेलकर्मी उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि राजभाषा हिंदी सरकारी कामकाज को सरल, सहज, प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा राजभाषा के प्रति सकारात्मक वातावरण को और मजबूत बनाने का आह्वान किया।

पूरे माह होंगे विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों के आयोजन

भावनगर मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा 01 से 30 सितंबर 2026 तक राजभाषा माह के अंतर्गत विभिन्न रचनात्मक, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माह के दौरान कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता तथा हिंदी वाक् प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं अधिकारियों के लिए हिंदी फोटो कैप्शन लेखन प्रतियोगिता एवं राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस समारोह एवं विचार गोष्ठी, विभागीय राजभाषा प्रदर्शनी प्रतियोगिता तथा राजभाषा माह समापन एवं भव्य पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित किए जाएंगे।

सभी प्रतियोगिताएं एवं प्रमुख कार्यक्रम मंडल कार्यालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 30 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले राजभाषा माह समापन समारोह में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

भावनगर मंडल में राजभाषा माह के आयोजन का उद्देश्य रेलकर्मियों में हिंदी के प्रति रुचि एवं जागरूकता को बढ़ावा देना तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक एवं प्रभावी प्रयोग को प्रोत्साहित करना है।